● वर्ष-4
● अंक-173
रायपुर, शुक्रवार 28 फरवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» इन देशों में सुरक्षा की नहीं होगी चिंता...

नगर निगम रायपुर के नव निर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण सम्पन्न

रायपुर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं समृद्ध शहर बनाने की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ करें कार्य : साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में नगर पालिक निगम, रायपुर के नव निर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में संपन्न हुआ। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने महापौर एवं सभी पार्षदों को वार्डवार शपथ दिलाई।

महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में शपथ ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदगण अटल विश्वास पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को पूरा कर रायपुर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं समृद्ध शहर बनाने की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेंगे। शपथ ग्रहण उपरांत महापौर मीनल चौबे ने मुख्यमंत्री साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्रीद्वय श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा, मंत्रीगण, पूर्व महापौर एवं विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, किरण देव, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

मस्जिद का सर्वे करने पहुंची एएसआई

संभल। उच्च न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम संभल जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंची। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट व अन्य पदाधिकारी भी साथ रहे। एहतियाती तौर पर मस्जिद के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। एएसआई की टीम ने करीब सवा घंटे तक मस्जिद की स्थिति का जायजा लिया।

इस रिपोर्ट के आधार पर ही जामा मस्जिद की पुताई और सजावट के लिए अनुमति का निर्णय तय हो सकेगा। संभल जामा मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसमें रमजान से पहले सफाई, पुताई और सजावट किए जाने का आग्रह किया गया था। बृहस्पतिवार की सुबह उच्च न्यायालय में इस याचिका पर सुनवाई की गई।

इसी सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने एएसआई की तीन सदस्यीय टीम को मस्जिद की वास्तविकता का आकलन कर शुक्रवार की सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में मस्जिद की स्थिति का आकलन करने के लिए एएसआई की टीम पहुंची। शाम 4.35 बजे एएसआई की टीम ने जामा मस्जिद में प्रवेश किया।

इस एएसआई की टीम में ज्वाइंट डायरेक्टर मदन सिंह चौहान, डायरेक्टर जुल्फिकार अली, मेरठ सर्किल के सुपरिटेंडेंटआर्कियोलॉजिस्ट विनोद सिंह रावत शामिल रहे। इस तीन सदस्यीय टीम ने 5.47 बजे तक मस्जिद की स्थिति का आकलन किया। एएसआई की टीम ने मस्जिद के हर हिस्से की बारीकी से जांच की। अब इसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश की जाएगी। उसके आधार पर निर्णय होगा कि अनुमति दी जानी है या नहीं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई और मरम्मत की जरूरत है या नहीं, इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) के तीन अधिकारी मुतवल्ली के साथ निरीक्षण करें। साथ ही इसकी रिपोर्ट शुक्रवार को न्यायालय में 10 बजे प्रस्तुत की जाए। इसके बाद ही न्यायालय रमजान शुरू होने से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई का निर्देश देने पर विचार करेगा।

न्यायालय ने यह भी कहा कि रमजान से पूर्व जो भी गतिविधि की जाए, एएसआई उसकी वीडियोग्राफी कराए। न्यायालय ने 28 फरवरी को फिर से मामले की सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन कमेटी की ओर से सिविल पुनरीक्षण में दाखिल त्वरित सुनवाई की अर्जी पर उक्त आदेश दिया।

मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता एसएफ नकवी ने दलील दी कि कई दशकों से मस्जिद की रंगाई-पुताई का काम कमेटी करती चली आ रही है। कभी एएसआई ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। रमजान का महीना एक मार्च से शुरू हो रहा है, इसलिए रंगाई पुताई किया जाना है। इस दौरान संरक्षित स्थल को न कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा और न ही किसी भी तरह का परिवर्तन किया जाएगा।

वहीं, एएसआई के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने दलील दी कि संरक्षित इमारत की मरम्मत, रंगाई-पुताई की जिम्मेदारी एएसआई की है। इसके बावजूद मस्जिद कमेटी के लोग एएसआई के अधिकारियों को परिसर में घुसने नहीं देते हैं। मस्जिद में रंगाई-पुताई की आवश्यकता है या नहीं, अदालत के आदेश पर निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।

वहीं अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने रंगाई-पुताई की अर्जी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि रंगाई-पुताई की आड़ में मस्जिद कमेटी हिंदू मंदिर की कलाकृतियों, चिह्नों और प्रतीकों को नष्ट कर देगी। मस्जिद एएसआई संरक्षित है, इसलिए मस्जिद कमेटी को रंगाई-पुताई की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने के बाद कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि मस्जिद एएसआई संरक्षित है। मरम्मत व रंगाई-पुताई का फैसला भी एएसआई के विवेकाधिकार पर है। न्यायालय के निर्देश पर एएसआई ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की। इसमें मदन सिंह चौहान संयुक्त निदेशक, जुल्फिकार अली निदेशक स्मारक, अधीक्षण पुरातत्वविद विनोद सिंह रावत शामिल हैं, जो मस्जिद के मुतवल्ली के साथ जांच कर शुक्रवार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

शिंदे नाराज, उद्धव कर रहे फडणवीस की तारीफ

मुंबई। महाराष्ट्र का राजनीति लगातार सुर्खियों में है। वहां, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर दरार की खबरें आई हैं। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा की जाने वाली बैठकों से बचते रहे हैं और इसी तरह की बैठकें आयोजित करने की एक समानांतर प्रक्रिया चला रहे हैं। हालांकि, शिवसेना दावा कर रही है कि गठबंधन के भीतर सबकुछ ठीक है। बावजूद इसके उनकी नाराजगी की खबरें आ ही जा रही है।

पिछले नवंबर में नतीजों के बाद भाजपा ने फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था, जिसके बाद शिवसेना प्रमुख शिंदे को उपमुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा था। शिंदे के समर्थकों का मानना ??है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके ढाई साल के कार्यकाल (जून 2022 से नवंबर 2024) के दौरान लिए गए फैसलों, विकास और कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही भाजपा, शिवसेना और राकांपा के गठबंधन को विधानसभा चुनाव में जीत मिली। शिवसेना नेताओं के अनुसार शिंदे उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टी के सहयोगियों और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उन्हें फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा बनने के लिए मना लिया था। रायगढ़ और नासिक जिलों के संरक्षक मंत्रियों को लेकर फैसले से दरार बढ़ती देखी।

उद्धव कर रहे तारीफ

विपक्षी शिवसेना (उबाठा) ने कुछ मंत्रियों द्वारा सुझाए गए निजी सहायकों के नामों को खारिज करने के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हालिया फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने अपने मुखपत्र 'सामना' में एक संपादकीय में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा। शिंदे प्रतिद्वंद्वी शिवसेना के प्रमुख हैं और उनके फडणवीस के साथ संबंध "तनावपूर्ण" बताए जा रहे हैं। जनवरी की शुरुआत में, सामना ने अप्रत्याशित रूप से फडणवीस की प्रशंसा की थी जब उन्होंने नक्सल प्रभावित गडचिरौली जिले का दौरा किया था और घोषणा की थी कि वहां इस्पात उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। 'सामना' के बुधवार के अंक में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है, "देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के शासन में अनुशासन को लेकर कड़े कदम उठाए हैं और उन्होंने (भ्रष्टाचार के) 'नालों की सफाई' शुरू कर दी है।" हाल के हफ्तों में यह दूसरी बार है जब शिवसेना (उबाठा) ने फडणवीस की प्रशंसा की है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा टैक्स फ्री की गई मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म छावा को आज वनवासी कल्याण समिति आश्रम के स्कूली बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ देखा। ये बच्चे उत्तर-पूर्व के असम और नागालैंड से हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ योग आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा के मार्गदर्शन में फिल्म दिखाने के लिए रायपुर के सिटी सेंटर मॉल, पंडरी लाया गया।

प्रमुख समाचार

भाजपा मतदाता सूची में कर रही है हेराफेरी-ममता

कोलकाता। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। चेतावनी देते हुए ममता ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को जल्द से जल्द दूर नहीं किया गया तो वह आयोग के दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया है। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मेरे पास सबूत हैं कि बंगाल में मौजूद एक एजेंसी बंगाल के मतदाताओं के नाम हरियाणा, गुजरात और अन्य राज्यों के लोगों के साथ बदल रही है, जबकि वोटर आईडी कार्ड नंबर वही है। ममता ने दावा किया कि, यह सीधे दिल्ली से किया जा रहा है। ऐसा करके, उन्होंने (भाजपा) महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीत हासिल की। आपकी दो जिम्मेदारियां हैं- भाजपा को हराना और बंगाल को फिर से जिताना।

मणिपुर में मैतेई ग्रुप ने सरेंडर किया लूटा हुआ सामान

नई दिल्ली। मणिपुर में एक मैतेई समूह अरामबाई टेंगोल के सदस्यों ने गुरुवार को राज्य सरकार को अपने हथियार सौंप दिए। यह कदम राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला द्वारा मणिपुर में लंबे समय से चली आ रही जातीय हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों के तहत सात दिनों के भीतर सभी समुदायों को स्वेच्छा से लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियार और गोला-बारूद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद आया है। सोशल मीडिया पर सामने आए दृश्यों में मैतेई समूह के सदस्यों को पिकअप ट्रकों के बेड़े में हथियार और गोला-बारूद ले जाते हुए दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि समूह ने 246 हथियार सरेंडर कर दिए हैं। हथियारों के अलावा उन्होंने सुरक्षाबलों के हेलमेट, जूते, वर्दी और दंगे के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली जैकेट भी सरेंडर की हैं। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 20 फरवरी को राज्य की जनता से अपील की थी कि वे लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को स्वेच्छा से सात दिनों के भीतर पुलिस को सौंप दें।

एमके स्टालिन कर रहे समाज बांटने की कोशिश: अश्विनी

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से तीन भाषा नीति का लगातार विरोध किया जा रहा है। गुरुवार को उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हिंदी ने कई भारतीय भाषओं को निगल लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने स्टालिन पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने की कोशिश से खराब शासन कभी नहीं छिपेगा। उन्होंने विपक्ष को भी घेरा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा कि समाज को बांटने की ऐसी कोशिशों से खराब शासन कभी नहीं छिप पाएगा। यह जानना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के नेता इस पर क्या कहते है। राहुल गांधी इस पर क्या कहेंगे? क्या वे हिंदी भाषी सीट के सांसद होने के नाते इससे सहमत हैं? तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने गुरुवार सुबह एक्स पर लिखा था कि क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है? भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊंनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, खरिया, खोरठा, कुरमाली, कुरुख, मुंडारी और कई अन्य भाषाएं अब अस्तित्व के लिए हांफ रही हैं।

पाकिस्तानी संसद में उठेगा मेजबानों की हार का मुद्दा

लाहौर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जल्द ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और टीम के खिलाड़ियों से चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबानों के खराब प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। इसकी जानकारी राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सरकार टीम के जल्दी बाहर होने से खफा है। 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रही पाकिस्तान की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में करारी हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व वाली टीम ने पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। इस दौरान उन्हें 60 रन से शिकस्त मिली थी। इसके बाद रविवार को पाकिस्तान का सामना भारतीय टीम से हुआ। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम ने विराट कोहली की शतकीय पारी की बदौलत चिर प्रतिद्वंद्वी को छह विकेट से हरा दिया। इस तरह पाकिस्तान का सफर टूर्नामेंट में समाप्त हो गया। गुरुवार को गत चैंपियन की टक्कर बांग्लादेश से होनी थी। लेकिन यह मुकाबला एक भी गेंद फेंके बिना बारिश के कारण रद्द हो गया। इस तरह दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। वहीं, न्यूजीलैंड और भारत की टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं।

ट्रंप का एलान- मैक्सिको और कनाडा पर लगेंगे टैरिफ

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह अगले मंगलवार से मैक्सिको और कनाडा पर कर (टैरिफ) लगाएंगे, साथ ही चीन से आयात पर मौजूदा 10 फीसदी टैरिफ दोगुना करेंगे। ट्रंप ने गुरुवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा कि फेंटेनाइल जैसी नशीली दवाओं की अमेरिका में अस्वीकार्य स्तर पर तस्करी की जा रही है और आयात कर अन्य देशकों को तस्करी पर रोक लगाने के लिए मजबूर करेंगे। ट्रंप ने लिखा, हम इससे अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए जब तक यह बंद नहीं हो जाता है या गंभीर रूप से सीमित नहीं हो जाता है, प्रस्तावित टैरिफ (जो चार मार्च से लागू होने वाले हैं) तय कार्यक्रम के अनुसार प्रभावी होंगे। उस तारीख पर चीन पर भी उसी दिन 10 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। बढ़ते टैरिफ की संभावना से पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है। उपभोक्ता आशंका जता रहे हैं कि अगर अमेरिका के दो बड़े व्यापिरक साझेदार कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाए जाते हैं तो महंगाई बढ़ सकती है और ऑटो क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। उधर, कई स्वास्थ्य समूहों और गैर-सरकारी संगठनों ने यूएसएआईडी की फंडिंग में कटौती करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले पर हैरानी और नाराजगी जताई।

–

फाइव आइज से कनाडा को बाहर करने की तैयारी में ट्रंप प्रशासन

कीर्तिवर्धन मिश्र

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद से ही कुछ देशों में हलचल मची है। इनमें सबसे अहम नाम अमेरिका के मित्र और सहयोगी देशों के हैं। हालांकि, जिस एक देश को ट्रंप ने सबसे ज्यादा निशाना बनाया है, वह अमेरिका के उत्तर में उसका सबसे करीबी पड़ोसी देश- कनाडा। चाहे आयात शुल्क लगाने से जुड़ी धमकियां हों या कनाडा से लगी सीमाओं पर अतिरिक्त सख्ती बरतने की चेतावनी या फिर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने से जुड़ा तंज। ट्रंप हर एक मौके पर कनाडा पर हावी होने की कोशिश में रहे हैं।

हालांकि, जिस ताजा मामले पर अमेरिका की तरफ से कनाडा के लिए सख्त रुख अख्तियार करने का इशारा किया गया है, वह उसकी सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। मामला है कनाडा को एक ऐसे फाइव आइज अलायंस से बाहर करने की चर्चा का। अगर कनाडा आगामी समय में इस गठबंधन से बाहर होता है, तो इसके कई दूरगामी असर हो सकते हैं। खासकर कनाडा की खुफिया और निगरानी क्षमताओं पर नकारात्मक असर पड़ना तय है।

फाइव आइज अलायंस क्यों ?

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और उसका साथ देने वाले देशों से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने एक खुफिया नेटवर्क स्थापित किया। अटलांटिक महासागर से बंटे इन दोनों देशों ने अलग-अलग तकनीकों से हजारों किलोमीटर दूर खुफिया जानकारी साझा करना शुरू किया था। इसका फायदा यह हुआ कि विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान की युद्ध नीति से जुड़े कई खुफिया कोड का पता लगा लिया गया। इस तरह अमेरिका और ब्रिटेन ने आगे भी खुफिया जानकारी साझा करना जारी रखा।

दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जब सोवियत संघ मजबूती से उभरा, तब अमेरिका और ब्रिटेन के इस गठबंधन ने खुफिया जानकारी साझा करना जारी रखा। 1946 में दोनों देशों ने अपने इस समझौते को आधिकारिक मान्यता दे दी। तब इसे ब्रिटिश-यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट (क्क्र) नाम दिया गया। इस पर दोनों देशों की सरकारों-सेनाओं और नौसेनाओं के खुफिया संचार विभाग की तरफ से हस्ताक्षर किया गया था। बाद में एक-एक कर के कुछ और देशों को भी इस समझौते का हिस्सा बनाया गया।

1948 में कनाडा इस समझौते से जुड़ने वाला पहला देश था। वहीं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस समझौते से 1956 में जुड़े। एक समझौते से पांच देशों के जुड़ने के बाद इसे फाइव आइज नाम दे दिया गया। यह गठबंधन अमेरिका-सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के समय काफी काम आया और अलग-अलग महासागरों में मौजूद देशों ने रूस की गतिविधियों की निगरानी कर अमेरिका को जबरदस्त फायदा पहुंचाया।

काम कैसे करता है?

फाइव आइज के पांच सदस्य देश अपनी घरेलू और विदेशी खुफिया एजेंसियों के जरिए अलग-अलग मुद्दों पर जानकारी साझा करते हैं। हालांकि, बदलते समय के साथ फाइव आइज की खुफिया गतिविधियों में भी बदलाव देखा गया है। खासकर सोवियत संघ में टूट के बाद इस गठबंधन आतंकवाद-कट्टरपंथी गतिविधियों और चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी नजर रखना शुरू कर दिया। फाइव आइज में न्यूजीलैंड को छोड़कर बाकी सभी देशों ने चीन के शिनजियांग में ईगुर मुस्लिमों के हालात को लेकर चिंता जताई है। इसके अलावा हॉन्गकॉन्ग और ताइवान में लोकतंत्र को तबाह करने की नीति को लेकर कड़ी निगरानी रखी है।

फाइव आइज से जुड़े देशों के बीच सहयोग तय करने के लिए इस गठबंधन ने एक परिषद- %फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल% भी स्थापित किया है। सितंबर 2016 में स्न्ढ्ढह्रक्रष्ट की स्थापना गैर-राजनीतिक निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संस्थान के तौर पर की गई थी। इसमें शामिल देश आपसी हितों वाले मुद्दों पर खुफिया जानकारी साझा करते हैं और एक-दूसरे से अहम मामलों पर संपर्क में रहते हैं।

फाइव आइज गठबंधन की गतिविधियां लंबे समय तक पर्दे के पीछे ही रहीं। ऐसे में इसके काम करने के तरीके, सुरक्षा और निजता को लेकर कोई खास जानकारी सामने नहीं आ पाई। 2013 में यह गठबंधन पहली बार विवादों में तब घिरा, जब अमेरिका की एक सुरक्षा एजेंसी- नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने कई गुप्त जानकारियां दुनिया के सामने रख दीं।

नक्सली हमले में घायल जवान को मिली राहत, सुकमा ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर। नक्सली हमले में घायल जवान के सुकमा ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आरक्षक दिनेश ओगरे को 2016 में बीजापुर में गोली लगी थी। 2018 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वह घायल हो गया था। उनके पैर में स्टील रॉड लगी थी। उन्होंने डीजीपी सर्कुलर का हवाला देकर अपने ट्रांसफर को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर कोर्ट ने स्थानांतरण और रिलीविंग आदेश पर रोक लगा दी है।

ग्राम नागरदा, जिला-सारंगढ़ निवासी दिनेश ओगरे दूसरी बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सकरी में आरक्षक (कॉन्सटेबल) के पद पर पदस्थ था। सेनानी, दूसरी वाहिनी ने आदेश जारी कर दिनेश ओगरे का स्थानांतरण सकरी, जिला-बिलासपुर से एफ कम्पनी सुकमा स्थानांतरण कर दिया था। उक्त स्थानांतरण (ट्रान्सफर) आदेश से क्षुब्ध होकर दिनेश ओगरे ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वाति सराफ के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी।

अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वाति सराफ ने हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि पूर्व में वर्ष 2016 में याचिकाकर्ता

पामेड़, जिला-बीजापुर में कान्सटेबल के पद पर पदस्थ था। हेलीपेड सुरक्षा के दौरान नक्सलियों द्वारा की गई गोलाबारी में याचिकाकर्ता के सिर में गोली लगी थी एवं वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसके साथ ही वर्ष 2018 में याचिकाकर्ता का एक मेजर एक्सीडेन्ट होने के कारण उसके बाएं पैर में स्टील की रॉड लगी है। उसे तेज चलने एवं दौड़ने में दिक्कत होती है। चूंकि जिला-सुकमा एक अति संवेदनशील एवं घोर नक्सली जिला है, चूंकि आवेदक की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति घोर नक्सली जिले में सेवा देने योग्य नहीं है। यदि याचिकाकर्ता घोर नक्सली जिला-सुकमा में ज्वाईन करता है तो नक्सलियों के टारगेट में होने के कारण याचिकाकर्ता की जान को खतरा है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पूर्व में 03।09।2016 को विशेष आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय एवं 18।03।2021 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा जारी सर्कुलर का हवाला दिया, जिसमें यह प्रावधान है कि नक्सली हमले में घायल जवानों से उनकी शारीरिक क्षमतानुसार कार्य लिया जाना चाहिए। ऐसे जवानों की पदस्थापना घोर नक्सली जिले में नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही समय-समय पर उनके स्वास्थ्य के संबंध में समुचित जानकारी प्राप्त किया जाना चाहिए परंतु याचिकाकर्ता के मामले में सेनानी दूसरी बटालियन ने इस वर्णित सर्कुलर का घोर उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता का घोर नक्सली जिला-सुकमा में स्थानांतण कर दिया था। उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने उक्त रिट याचिका की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता का जिला-सुकमा के लिए जारी स्थानांतरण आदेश एवं रिल्हीविंग आदेश पर स्टे लगा दिया।

ग्राम बंडा के पास से 5 किलो वजनी आईईडी बरामद

सुकमा। थाना कोंटा क्षेत्र अंतर्गत कोंटा-गोलापल्ली मार्ग पर ग्राम बंडा के पास नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 5 किलोग्राम आईईडी बरामद कर मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। इस आईईडी को खोज निकाला। सुरक्षाबल को मुखबिर की सूचना और डिमाइनिंग अभियान के तहत सीआरपीएफ की 228वीं बटालियन और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान के दौरान गुरूवार को 5 किलोग्राम आईईडी बरामद कर थाना कोंटा में विधिसम्मत कार्रवाई की गई।

सुरक्षाबलों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसे को विफल कर नक्सलियों के नापाक इरादों पर पानी फे दिया है। पुलिस प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे संदिग्ध वस्तुओं की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें, ताकि नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

2 नक्सली मिलिशिया प्लाटून सदस्य ने किया आत्मसमर्पण

बीजापुर। नियद नेल्ला नार योजना एवं अंदरूनी इलाकों में लगातार खोले जा रहे सुरक्षा कैंपों से सुरक्षाबलों की कार्यवाही से बढते दबाव के फलस्वरूप भैरमगढ़ एरिया कमेटी एवं जगरगुण्डा एरिया कमेटी मे सक्रिय 2 नक्सलियों सुखराम सोढ़ी ऊर्फ सुकडु पिता मंगडू सोढ़ी उम्र 27 वर्ष निवासी केशकुतुल थाना भैरमगढ़, पदनाम केशकुतुल आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य, वर्ष 2015 से सक्रिय एवं नारू ईरपा ऊर्फ नारायण पिता विरैया उम्र 36 वर्ष निवासी बलम नेण्ड्रा थाना बासागुड़ा, मिलिशिया प्लाटून सदस्य, वर्ष 2021 से सक्रिय ने पुलिस उप महानिरीक्षक केरिपु बीजापुर देवेन्द्र सिंह नेगी , पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ। जितेन्द्र कुमार यादव, कमांडेंट 199 आनंद कुमार, कमांडेंट 210 कोबरा अशोक कुमार, अति।पुलिस अधीक्षक नक्सल अभियान मयंक गुर्जर, अति।पुलिस अधीक्षक युलैण्डन यार्क, उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स सुदीप सरकार, उप पुलिस अधीक्षक डीआरजी विनीत साहू के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।

दोनो आत्मसमर्पित नक्सली वर्ष 2015 बाल संगम सदस्य के पद पर कार्य किया, वर्ष 2016 से संगठन में मिलिशिया प्लाटून सदस्य के पद पर सक्रिय रहे। आत्मसमर्पित करने वाले उक्त नक्सलियों को आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपये के नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।बीजापुर जिले में इस वर्ष 2025 में अब तक कुल 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है।

घर के बाहर सो रहे राम सिंह कंवर की हत्या, दीवार पर लिखे धमकी भरे संदेश

कोरबा। कोरबा जिले के उरगा थाना अंतर्गत ग्राम नवापारा निवासी जितेंद्र कंवर के घर की दीवारों पर जो धमकी भरे संदेश लिखे हैं वो इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। घर के बाहर सो रहे राम सिंह कंवर को मौत की नींद सुलाने वाला आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, हालांकि पुलिस अपराध कायम कर उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। हत्या के दिन उसने मृतक के पुत्र जगदीश की हत्या करने धमकी भरा संदेश लिखा था। कल तक गांव के लोग इसे सामान्य रुप से देख रहे थे मगर जिस तरह से एक बार फिर से उसने दिवारों पर अपने मन की बात लिखी है उससे पूरा गांव दहशत में है।

खुद को कलयुग के कल्की का अवतार बताते हुए अज्ञात सख्श ने लिखा है कि राम सिंह की मौत के बाद पांच और लोगों की हत्याएं होंगी, गांव में शराब को बंद करो, अगली वारदात पकरिया गांव से होगी, इस बार मोनू की बारी है, धोखा देना है।

पुलिस को भी धमकाते हुए उसने लिखा है कि अगर पुलिस उसकी खोज करेगी तो उन्हें भी दिक्कत होगी। इन तमाम धमकी भरे संदेश को भले ही पुलिस गंभीरता से ना ले लेकिन गांव के लोग काफी डरे हुए हैं, खासकर मोनू नाम का युवक जिसकी मौत का दिन अज्ञात आरोपी ने मुकर्रर कर दिया है। इस संबंध में कोरबा सीएसी ने कहा है कि अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है जल्द पकड़ लिया जाएगा।

दीवार पर धमकी भरा संदेश लिखने वाला व्यक्ति कौन है,कहां का रहने वाला इस बात का पता नहीं चल सका है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपी की पहचान करना है और उसके बाद दूसरी चुनौती उसे पकड़ने की है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस तरह के धमकी भरा संदेश लिखने वाले आरोपी को कब तक पकड़ पाती है।

कुछ दिन पहले राम सिंह घर के आंगन में सो रहा था जिसे अज्ञात हत्यारे ने हमला कर दीवाल पर संदेश लिखा था, घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई है अब हत्यारे ने फिर से गांव में संदेश लेकर सनसनी फैला दी है।

1 मार्च को महापौर का शपथ ग्रहण समारोह

उपमुख्यमंत्री सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल

जगदलपुर। नगर निगम के महापौर संजय पांडे के साथ पार्षदगण शनिवार 1 मार्च को दंतेश्वरी मंदिर के सामने सुबह 10.30 बजे पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। आज गुरूवार सुबह कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने महापौर संजय पांडे सहित निगम आयुक्त निर्भय साहू अपने टीम के साथ पहुंचे थे।

शनिवार को शपथ ग्रहण मौके पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। जबकि प्रदेश अध्यक्ष व विधायक जगदलपुर किरण देव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। समारोह में कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों में मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप, चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, निवर्तमान

महापौर सफिरा साहू,वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीनिवास राव मद्दी, कमलचंद्र भंजदेव, पूर्व विधायक संतोष बाफना, जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पांडे सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही सभी समाज प्रमुख, अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के के नेता, कार्यकर्ता सभी मीडिया के साथी मौजूद रहेंगे।

नगर निगम के कुल 48 सीटों में से इस बार भाजपा ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की है जबकि कांग्रेस को 16 और निर्दलीय को 2 सीटें मिली है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद शहर के विकास व नागरिकों के लिए कई अहम बातें व घोषणाएं हो सकती है। नवनिर्वाचित महापौर संजय पांडे ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जिन कामों को बर्बाद किया है, उसे प्राथमिकता में पूरा किया जाएगा। जो कहा है वो कर के दिखाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प मिशन 2047 विकसित भारत के तहत हम दीर्घ और अल्पकालीन योजना बनाकर शहर को बेहतर स्वरूप देंगे।

मेडिकल स्टोर खुलवाने के नाम पर ऐंठी मोटी रकम, आरोपी सलाखों के पीछे

जशपुर। जशपुर पुलिस ने एक गंभीर महिला अपराध के मामले में आरोपी जाहिद हुसैन (उम्र 29 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी पर थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में धारा 366, 376(2) तथा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

थाना सिटी कोतवाली के तहत आने वाले मामले में प्रार्थीया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2023 से आरोपी जाहिद हुसैन ने प्रार्थिया से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने प्रार्थिया को अंबिकापुर में स्थित एक किराए के घर में रखकर शारीरिक शोषण किए। इसके अतिरिक्त, आरोपी ने महिला से मेडिकल स्टोर का लाइसेंस दिलाने के नाम पर डेढ़ से ढाई लाख रुपए ठगी की। जब प्रार्थिया ने आरोपी से शादी की पेशकश की और ठगी से लिए गए धन की वापसी की मांग की, तो आरोपी ने टालमटोल कर उसकी भावना को ठेस पहुँचाई।आरोपी जाहिद थाने में मामला दर्ज होने की भनक लगते ही फरार हो गया था।

पुलिस को मुखबीर से मिली सूचना के अनुसार, आरोपी जाहिद हुसैन ग्राम सन्ना में था। सिटी

कोतवाली पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को ग्राम सन्ना से हिरासत में लेकर लाया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकश ने कहा कि जशपुर पुलिस महिला-संबंधी अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और अपराध सिद्ध होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजना हमारा कर्तव्य है। अपराध की गंभीरता और सभी उपलब्ध सबूतों के आधार पर, आरोपी जाहिद हुसैन के खिलाफ धारा 366 (शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी), 376(2) (महिला का शारीरिक शोषण) तथा 420 (ठगी) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस विवेचना में जुटी है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

माघ महीने में होता है असली कुंभ : अविमुक्तेश्वरानंद

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में महाकुंभ 2025 पर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अभी तक जो महाकुंभ चला वह सरकारी महाकुंभ था। असली कुंभ तो माघ महीने में होता है। आगे उन्होंने कहा कि माघ महीने की पूर्णिमा को ही इसका समापन हुआ था। माघ महीने की पूर्णिमा के दिन ही सभी कल्पवासी वहां से चले गए थे। तभी कुंभ का समापन हुआ था। दरअसल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 45 दिवसीय महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का आना जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि महाकुंभ 2025 के दौरान 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई थी और 26 फरवरी को महाकुंभ का आधिकारिक समापन हो गया। इसके अलावा मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, और माघी पूर्णिमा को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई।

ट्रक का टायर फटने के बाद उसमें अचानक लगी आग

बालोद। रायपुर-जगदलपुर मुख्य मार्ग में स्थित ग्राम जगतरा में टोल प्लाजा के पास एक ट्रक का टायर फटने के बाद उसमें अचानक आग लग गई। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है। देर शाम ट्रक में लगी आग का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस थाना पुरुर थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि जगदलपुर की ओर से आ रही एक ट्रक का पिछला टायर फटने के बाद ट्रक मे आग लग गई। ट्रक में आयरन गिट्टी लोड थी। यह घटना गुरुर ब्लॉक से गुजरे नेशनल हाईवे 30 में ग्राम जगतरा में टोल प्लाजा के पास की है। जहां दिन भर सैकड़ों की संख्या में वाहन गुजरते हैं ऐसे में ट्रक में आग लगने के बाद तत्काल जिला मुख्यालय धमतरी और बालोद से अग्निशमन वाहन को बुलाया गया, जहां काफी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया। जिस ट्रक में आग लगी थी उस ट्रक का वाहन चालक एवं परिचालक पूरी तरह से सुरक्षित है, हालांकि घटना के बाद लगभग 2 घंटे तक मुख्य मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की कतारे लग गई थी।

14 उद्योगों पर 10.51 लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना

रायगढ़। रायगढ़ जिले में कच्चे माल, उत्पाद और अपशिष्ट परिवहन के दौरान पर्यावरणीय सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच दल द्वारा बीते सप्ताह की गई निरीक्षण कार्रवाई में 14 उद्योगों पर कुल 10.51 लाख रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क अधिरोपित किया गया है। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी श्री अंकुर साहू ने बताया कि 15 से 21 फरवरी 2025 के दौरान गठित जिला स्तरीय जांच कमेटी ने चंद्रपुर, कोडातराई, हमीरपुर, ढिमरापुर, तमनार, घरघोड़ा और पलगढ़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कच्चे माल, उत्पाद और अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान कई वाहन बिना तारपोलिन कवर के खुले में कच्चा माल परिवहन करते पाए गए, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण फैलने की आशंका बढ़ गई। इसके अलावा, कुछ वाहनों में 5 सेमी. फ्री बोर्ड स्पेस का अभाव था, जिससे सामग्री गिरने का खतरा था। कई वाहनों पर संबंधित नोडल अधिकारी का नाम अंकित नहीं था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यात्री सुविधाओं पर तोखन ने की रेल महाप्रबंधक से चर्चा

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू से उनके आवास पर सौहार्दपूर्ण भेंट की।

इस दौरान रेलवे से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और अमृत भारत स्टेशन योजना की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा, बुधवारी बाजार, कटघोरा-डोंगरगढ़ रेलवे लाइन तथा बिलासपुर एवं उसलापुर स्टेशनों पर हो रहे रेल विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे को और अधिक सक्षम बनाने के लिए गतिशक्ति परियोजनाओं की प्रगति पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें रेलवे के विकास कार्यों को गति देने पर सहमति बनी।

नवनिर्वाचित महिला सरपंच का निधन, गांव में मातम

जांजगीर चांपा। बलौदा ब्लॉक के बेहराडीह में नवनिर्वाचित महिला सरपंच का निधन होने से गांव में शोक की लहर है। नम आंखों से ग्रामीणों ने सरपंच को विदाई दी। उनका अंतिम संस्कार आज गांव में किया गया। बता दें कि 24 फरवरी को जीत के बाद नवनिर्वाचित सरपंच भगवती मरकाम ने आभार रैली निकाली थी, इस दौरान उनकी तबियत अचानक बिगड़ी थी। जानकारी के मुताबिक, 23 फरवरी की रात पंचायत चुनाव के परिणाम की घोषणा हुई थी। इस चुनाव में भगवती चंद्रकुमार मरकाम सरपंच निर्वाचित हुई। जीत की खुशी में 24 फरवरी को गांव में आभार रैली निकाली गई। रैली के दौरान सरपंच भगवती की तबियत बिगड़ गई। उन्हें बिलासपुर अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 26 फरवरी की शाम डाक्टर ने उसे मृत घोषित किया। सरपंच के निधन के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है।

सिरपुर की कमार जनजातीय महिलाओं के लिए वरदान

- आर्थिक तंगी से आत्मनिर्भरता तक का सफर

महासमुंद। सुशासन का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाना होता है। जब कोई नीति या योजना समाज के वंचित वर्गों तक प्रभावी ढंग से पहुँचती है, तो उसका असर न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे समुदाय पर पड़ता है। ऐसी ही एक पहल महतारी वंदन योजना ने महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र की कमार जनजातीय महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की नई राह दिखाई है।

सिरपुर की रहने वाली श्रीमती केंवरा कमार पहले परंपरागत बांस शिल्प कारीगरी पर निर्भर थीं। यह उनकी आजीविका का मुख्य साधन था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनका व्यवसाय ठप पड़ गया था। सीमित संसाधनों और बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण

उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। मगर महिला एवं बाल विकास विभाग से 1000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि मिलने के बाद उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। इस आर्थिक सहयोग से उन्होंने बांस, रस्सी और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदनी शुरू की, इससे उनका व्यवसाय फिर से अच्छा चल रहा है, और अब वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में सक्षम हो रही हैं।

इसी तरह सिरपुर की ही रहने वाली भामिनी गोस्वामी इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटी टांसी गोस्वामी के भविष्य को संवार रही हैं। हर माह मिलने वाली 1000 रुपये की सहायता राशि को वे सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर रही हैं। यह छोटी-सी बचत उनकी बेटी के लिए एक मजबूत आर्थिक संबल बन रही है, जो आगे चलकर उसकी उच्च शिक्षा और विवाह में सहायक सिद्ध होगी। भामिनी कहती हैं, पहले हमारे पास इतनी बचत नहीं होती थी कि हम अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच सकें, लेकिन महतारी वंदन योजना ने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य दे सकें। महतारी वंदन योजना केवल एक आर्थिक सहायता योजना भर नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण का आधार भी बन रही है। खासकर दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं।

जेब में रखा मोबाइल ब्लास्ट अस्पताल पहुंचा युवक

बेमेतरा। जिले में मोबाईल ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है। मोबाइल युवक की जेब में ब्लास्ट हो गया। जिससे युवक का हाथ और जांघ झुलस गया है। बताया जा रहा है कि जिले में मोबाइल ब्लास्ट की पहली घटना है। घटना बुधवार की है। जब लोलेसरा गांव का युवक नीतीश कुमार वर्मा सोमनाथ धाम में लगे मेला में शामिल होने जा रहा था। तभी उसके जेब में रखा एन्ड्रॉयड मोबाइल अचानक ब्लास्ट हो गया। जिससे युवक को चोट आई है। घायल युवक को बेमेतरा के शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक की हालत सामान्य बताई जा रही है। उसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। युवक के मित्र राहुल वर्मा ने बताया कि मेला जाते वक्त नीतीश की जेब में रखा मोबाइल ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। मिट्टी डालकर मोबाइल से आग बुझाई गई है।

धान खरीदी में गड़बड़ी, प्रभारी और डाटा ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में खाद्य विभाग ने धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर केंद्र प्रभारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। भौतिक सत्यापन के दौरान 23 लाख 25 हजार 930 रू की गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। इस मामले में जांच के बाद अब मल्हार समिति प्रभारी संतु यादव और ऑपरेटर देवेंद्र बंजारे के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है।

दरअसल, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान मल्हार समिति में नियमित जांच के दौरान धान उपार्जन केन्द्र के भौतिक सत्यापन में 5267 धान की बोरियो में से 4497 बोरी में मानक धान, 600 बोरी में भूसी रेती मिश्रित एवं 170 बोरी में धान व भूसी मिश्रित मिला। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में केवल 4497 बोरी मानक धान पाया गया। 13 फरवरी को

जांच के दौरान धान व भौतिक रूप से प्राप्त मानक धान सत्यापन करने पर प्राप्त धान 4497 बोरी का अंतर करने पर 18759 बोरी धान कम पाया गया।

अब खाद्य विभाग ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने वाले उपार्जन केन्द्र मल्हार के प्रभारी समिति प्रबंधक/धान खरीदी प्रभारी संतू कुमार यादव एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर देवेन्द्र बंजारे के खिलाफ मल्हार थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है।

संक्षिप्त समाचार

महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर सीएम साय ने सीएम योगी को दी बधाई

रायपुर। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ के

समापन के बाद आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सफल आयोजन के लिए बधाई दी है। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से दूरभाष पर चर्चा कर प्रयागराज महाकुंभ के ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन के सफल समापन पर उन्हें हार्दिक बधाई दी। यह भव्य और विराट आयोजन हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और परंपराओं की अद्भुत झलक प्रस्तुत करता है। साथ ही, मैंने छत्तीसगढ़ राज्य के श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला परिसर में साढ़े चार एकड़ भूमि आवंटित करने हेतु उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। इस मंडप में छत्तीसगढ़ के 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने नि:शुल्क आवास, भोजन एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उठाया और संगम में स्नान का पुण्य प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रबंधन एवं संत-समाज के सान्निध्य में संपन्न हुए इस भव्य आयोजन के लिए पुन: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं एवं साधुवाद।

ईडी दफ्तर पहुंचे कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री

गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दफ्तर पहुंचे हैं। दरअसल, सुकमा और कोंटा में बने कांग्रेस भवन के निर्माण के संबंध में ईडी प्रभारी महामंत्री को जानकारी के लिए तलब किया गया है। उहोने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सुकमा और कोंटा के राजीव भवन के निर्माण का पाई-पाई का हिसाब ईडी को देंगे। 30 पन्नों की जानकारी तैयार है। चार बिंदुओं पर पूरी जानकारी तैयार कर ली है। बता दें कि सुकमा और कोंटा में निर्मित कांग्रेस भवन के लिए मिले नोटिस का जवाब देने कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी ने मंगलवार को नोटिस भेजकर जवाब के लिए आज तलब किया था। भवन के निर्माण के संबंध में जानकारी के लेने के लिए ईडी की टीम मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंची थी। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू से बंद कमरे में पूछताछ के बाद टीम ने चार बिंदुओं में गुरुवार तक जवाब मांगा था।

गंगाजल से नगर निगम का शुद्धिकरण दबाव में काम कर रही नई मेयर : ढेबर

रायपुर। गंगाजल से नगर निगम के

शुद्धिकरण के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि यह सभी वर्ग के पार्षदों का अपमान है। शपथ ग्रहण को लेकर ढेबर ने कहा, प्रोटोकॉल के तहत पूर्व महापौर, पूर्व सभापति और कांग्रेस के पार्षदों को फोन किया जाना था। किसी के पास कोई फोन नहीं आया। पूर्व महापौर ढेबर ने महापौर मीनल चौबे को बधाई देते हुए कहा कि वो बड़े नेता के दबाव में निर्णय ले रही है। केवल शपथ ग्रहण का कार्ड भेजने की औपचारिकता पूरी की गई। ऐसे में शपथ ग्रहण में जाने का सवाल ही नहीं उठता।

निकाय चुनाव में हार की समीक्षा के लिए आज कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों

में कांग्रेस की हार की समीक्षा के लिए 28 फरवरी को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसमें कार्यकारिणी सदस्यों के साथ प्रभारी सचिव जारिता लैतफलांग, संपत कुमार और सह प्रभारी विजय जांगिड़ भी मौजूद रहेंगे। नगरीय निकाय चुनावों में हार और पंचायत चुनाव में जीत के दावों को लेकर हो रही बैठक में एक बार फिर पीसीसी अध्यक्ष को हटाने की चर्चा के बीच होने वाली बैठक को अहम माना जा रहा है। निकाय चुनाव में हार के बाद कांगेस के कई नेताओं ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया है। निकाय चुनाव में हार की बड़ी टिकट वितरण में गड़बड़ी को माना गया है, इसके लिए पार्टी में हावी गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बैठक में इन सभी पर विचार करने के बाद संगठन को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा राजीव भवन में ईडी के टीम के पहुंचने और सुकमा और कोंटा में निर्मित कांग्रेस भवन को लेकर दिए गए समन को संगठन ने गंभीरता से लिया है। बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है।

सदन में उठा जल स्रोत विहीन गांवों में टंकी और पाइप लाइन बिछाने का मुद्दा

■ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर घिरे मंत्री साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने जल स्रोत नहीं होने के बाद भी पाइपलाइन बिछाने और टंकी बनाने पर सवाल करते हुए कहा कि यह खुला करप्शन है। क्या उन अफसरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी? पीएचई मंत्री अरुण साव ने संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। यह भी पढ़ें = कांग्रेस प्रभारी महामंत्री गेंदू पहुंचे ईडी कार्यालय, सुकमा और कोंटा में बने कांग्रेस भवनों की देंगे जानकारीज

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन पर सवाल करते हुए कहा कि चार महीने पहले मुझे विस्तृत जानकारी देने की बात मंत्री ने कही थी, लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया गया कि कितने गांव में जल स्रोत नहीं है? कितने गांवों में पाइपलाइन और टंकी बनाई गई है?

पीएचई मंत्री ने कहा कि हर स्कीम में स्रोत आइडेंटिटिफ़ाई था। 653 गाँवों में पाइपलाइन और टंकी बनाई गई है। ग्राम सभा ने अनुमोदन किया है। अप्रैल 2023 में हैंडपंप का टेंडर हुआ। इसके बाद काम का विश्लेषण कर एक साथ सरकार ने छह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया था।

भाजपा विधायक ने पूछा कि जब डीपीआर बनाया गया तब जल स्रोत नहीं पाया गया था। मंत्री ने बताया कि हर एक डीपीआर में जल स्रोत चिन्हांकित था। इस पर विधायक ने कहा कि डीपीआर में जल स्रोत नहीं होने के बाद भी

पाइपलाइन बिछाई गई। टंकी बनाई गई। यह खुला करप्शन है। क्या उन अफसरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी? मंत्री ने बताया कि किसी भी ठेकेदार का 70 फीसदी काम नहीं होने की स्थिति में राशि का भुगतान नहीं होगा। जल स्रोत के मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा पूर्व सत्रों में किसी भी मंत्री ने सदस्यों के पूछे गए सवालों पर जानकारी भेजने का आश्वासन करने के बाद भी जानकारी नहीं भेजी जाती है तो ये उचित नहीं है। मंत्रियों को उचित समय में जानकारी भेजनी चाहिए।

इसके पहले भाजपा विधायक गोमती साय ने पत्थलगांव क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य पर ठेकेदार पर हुई कार्रवाई के संबंध में सवाल किया। पीएचई मंत्री अरुण साव ने बताया कि जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर सरकार गंभीर है। 19656 गांव को सम्मिलित कर योजना बनाई गई है। 2024 तक योजना निर्धारित थी, लेकिन सरकार ने इसे 2028 तक बढ़ाया है।

मंत्री ने बताया कि 80.03 फीसदी नल कनेक्शन हो चुका है। ट्यूबेल खनन 2023 से शुरू हुआ है। अभी तक आधा खनन हो चुका है। 2711 पानी टंकियों का निर्माण किया गया है। 351 ठेकेदारों का कार्य निरस्त किया है, वहीं 15 ठेकेदारों को बाहर किया गया है। विधायक ने लंबित कार्य के लिए समयसीमा तय करने की मांग की, जिस पर मंत्री ने पूरी ताकत से कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया।

जीवन मिशन योजना अंतर्गत विधानसभावार राशि प्रदाय नहीं की जाती

विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में केन्द्र द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंर्तगत राज्य को प्रदाय की गई राशि का मामला पुन्नूलाल मोहले ने उठाया। उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण अरूण साव ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत विधानसभावार राशि प्रदाय नहीं की जाती है अपितु जिले को जल जीवन मिशन के कार्यों के भुगतान हेतु वित्तीय आहरण सीमा जारी की जाती है। मुंगेली जिले को वर्ष जनवरी, 2022 से दिनांक 31/01/25 तक जारी वित्तीय आहरण सीमा में केन्द्राश राशि रू. 16797.71 लाख है। राज्य सरकार का इस योजना में राज्यांश, केन्द्रांश के समतुल्य है। उक्त योजना के माध्यम से मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में कुल 211 नवीन पानी टंकी का निर्माण किया गया है।

कौशिक ने पूछा कि कुल कितने घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कितना लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है एवं कितना शेष है? साव ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना में विधानसभा क्षेत्र मुंगेली अन्तर्गत कुल 67954 घरों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 62385 घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 5569 घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य शेष है।

मूणत ने उठाया अमृत मिशन योजना के तहत निगम रायपुर द्वारा कराये गये ओवर लेपिंग का मामला

रायपुर। रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने नगर पालिका निगम रायपुर हेतु अमृत मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृति परियोजना में 45 वार्डों को सम्मिलित किया गया था, जिसका समस्त कार्य पूर्ण है तथा शेष 25 वार्ड इस योजना से वंचित हैं ? यदि हां तो अमृत मिशन योजना का डी.पी.आर. कब एवं कितने वार्डों के लिए तैयार किया गया था? का मामला प्रश्नकाल के दौरान उठाया। उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण अरूण साव ने सदन को बताया किअमृत मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृति परियोजना में 45 वार्डों को पूर्ण व आंशिक रूप से

सम्मिलित किया गया था तथा शेष 25 वार्ड इस योजना से वंचित हैं। अमृत मिशन योजना का डीपीआर दो चरणों में वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में तैयार किया गया था।

मूणत ने पूछा कि ऐसे 45 वार्ड, जिनमें अमृत मिशन योजना के तहत समस्त कार्य पूर्ण हैं, क्या वहां पूर्व से भी टंकी बनी हुई थी, डिस्ट्रीब्यूशन लाईन डली हुई थी तथा राईजिंग लाईन भी डली हुई थी? यदि हां, तो इन 45 वार्डों में ओवर लेपिंग नहीं हुई तथा पुरानी टंकी की पाईप लाईन (वितरण तथा राईजिंग को) छोड़कर नई अलग से पाईप लाईन बिछायी गयी है संबंधी प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया गया तथा इस प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन किस स्तर के अधिकारी ने कब किया?

मंत्री साव ने बताया किजी हां। 45 वार्ड जिनमें अमृत मिशन योजना के तहत् समस्त कार्य पूर्ण है, वहां पूर्व से निर्मित 12 टंकियों हेतु डिस्ट्रीब्युशन एवं राईजिंग लाईन डली हुई थी। योजनांतर्गत राईजिंग लाईन केवल नयी टंकियों हेतु ही बिछायी गयी है, इसमें किसी भी प्रकार की ओव्हर लेपिंग नहीं हुई है। डिस्ट्रीब्युशन पाईपलाईन में ओवर लेपिंग ना हों इसलिये संबंधित जोन क्षेत्र के जल विभाग में पदस्थ तत्कालीन उप अभियंता एवं सहायक अभियंता तथा लाईन मेन से जानकारी संकलन कर कार्य का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निकाय द्वारा तैयार किया जाकर, पाईपलाईन विस्तारीकरण कार्य कराया गया है। इस संबंध में निकाय द्वारा कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।

पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन की स्थिति खराब

भूपेश बघेल ने कहा- बिना तैयारी के आ रहे मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायक भी असंतुष्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने विभागीय मंत्री से सवाल किए, लेकिन मंत्री के पास संतोषजनक जवाब नहीं था। इस पर विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, सच्चाई यह है कि पूरे प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। नल जल विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। एक ही विभाग से

विधायकों को तीन-तीन बार सवाल पूछने पड़ रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी असंतुष्ट हैं, तो समझ जाइए कि विभाग की स्थिति क्या होगी?

भूपेश बघेल ने मंत्री की तैयारी पर भी सवाल उठाते हुए कहा, मंत्री बिना तैयारी के ही सदन में आ रहे हैं, जो जनता के प्रति उनकी लापरवाही को दर्शाता है।

लोगों का ध्यान भटकाने ईडी की कार्रवाई

बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी और आईटी का काम अब कांग्रेस को बदनाम करने का रह गया है। अगर हिम्मत है तो दिल्ली में बने भाजपा कार्यालय का हिसाब लिया जाए। छत्तीसगढ़ के कुशाभाऊ ठाकरे और एकात्म परिसर कार्यालय का भी हिसाब लिया जाए।

पीएम मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यो दिए 21 लाख मिलियन डॉलर : भूपेश बघेल

रायपुर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा के दौरान पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया। बघेल ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 लाख मिलियन डॉलर दिए हैं। इसका जवाब प्रधानमंत्री और भाजपा को देना चाहिए। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बघेल ने कहा कि जनता जवाब का इंतजार कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि जब राज्य सरकार खुद ये मान रही है कि प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है तो वो चुप क्यों है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, धर्मांतरण रोकने के उपाए क्यों नहीं किए जा रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि 21 लाख मिलियन डॉलर अपने मित्र मोदी को दिए हैं। भाजपा को इस बात का जवाब देना चाहिए। बघेल ने कहा कि देश की बुद्धिजीवी ये जानना चाहती है कि आखिर क्यों पैसे दिए गए। बघेल ने कहा कि हर विषय पर बोलने वाली बीजेपी और उसके पीएम आज चुप क्यों हैं। भूपेश बघेल ने इस चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। भूपेश बघेल ने कहा आज तक प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट इतना बड़ा आरोप किसी ने नहीं लगाया है। एक इतने बड़े देश के राष्ट्रपति कुछ कहते हैं तो उसकी बात का वजन होता है। इसपर बीजेपी और पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए।

भूपेश बघेल ने कहा कि जब विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण हो रहा है तो फंडिंग की जानकारी केंद्र सरकार को भी होगी। बिना किसी जानकारी के फंडिंग अपने देश में नहीं आ सकती है। बघेल ने कहा कि जब सीएम खुद मानते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है तो फिर उसे रोकने के उपाए क्या किए जा रहे हैं, ये बताना चाहिए।

1 लाख से ज्यादा राजस्व प्रकरण लंबित : चंद्राकर

भाजपा विधायक ने कहा- भगवान भरोसे है 'भुईया पोर्टल'

रायपुर। विधानसभा में गुरुवार को राज्य में लंबित राजस्व प्रकरणों का मुद्दा गूंजा, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने स्थिति की गंभीरता का जिक्र करते हुए कहा कि 'भुईया पोर्टल' भगवान भरोसे है। स्पीकर डॉ। रमन सिंह ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए विभागीय मंत्री से कहा कि राजस्व प्रकरणों की स्थिति वेंटिलेटर पर जाने से पहले दुरुस्त कर लें।

विधानसभा में विधायक अजय चंद्राकर, उमेश पटेल, शकुंतला पोर्ते ने ध्यानाकर्षण के जरिए लम्बित राजस्व मामला का मुद्दा उठाया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- भुईंया पोर्टल भी लगता है कि किसानों को परेशान करने के लिए बनाया गया है। 35 फीसदी डाटा की ग़लत एंट्री की है।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- भू-अभिलेख में त्रुटि सुधार का अधिकार एसडीएम और तहसीलदार के पास है। पूर्व सरकार ने इसे एसडीएम तक सीमित कर दिया था। नए संशोधन में यह अधिकार अब तहसीलदार को भी दिया गया है। है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपनी जमीन संबंधित जानकारी देख सकता है। राज्य में 1 लाख 49 हज़ार 479 राजस्व प्रकरण लंबित हैं।

इस पर अजय चंद्राकर ने कहा- लोक सेवा गारंटी अधिनियम का राजस्व विभाग पालन नहीं कर रहा है। लोक सेवा अधिनियम का पालन नहीं करने पर कितने अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। राजस्व मंत्री ने बताया कि लंबित प्रकरण में अपील करने पर सुनवाई होगी। लम्बित प्रकरणों की संख्या बढ़ी है। बजट सत्र के बाद राजस्व पखवाड़ा चलेगा। लंबित प्रकरणों की सुनवाई होगी।

अजय चंद्राकर ने पूछा- भुईया पोर्टल में होने वाली त्रुटि कौन सुधारता है? राजस्व मंत्री ने बताया कि पोर्टल का संचालन एनआईसी करता है। त्रुटि सुधारने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- भुईया पोर्टल में होने वाली त्रुटि को सुधारने के लिए समयसीमा सात दिनों की है लेकिन इसे सुधारा नहीं जा रहा है। भुईया पोर्टल क्या भगवान भरोसे है? उन्होंने पूछा- राजस्व प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद क्या कार्रवाई की गई?

मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- राजस्व प्रकरणों को लेकर शिविर का आयोजन किया गया था।

अजय चंद्राकर ने कहा- राजस्व प्रकरण निपटाने के लिए एक भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। भुईया पोर्टल की त्रुटि भी तीन-चार महीने तक नहीं सुधारी जा रही है। एनआईसी से मिलकर आनलाइन त्रुटि करवाई जाती है।

स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा- लंबित राजस्व प्रकरणों के लिए यह सुनिश्चित कि जाए कि कार्ययोजना बनाकर विभाग काम करे। इस पर राजस्व मंत्री ने कहा- जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने पूछा- राजस्व प्रकरणों को लेकर किसानों की अपील के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। अकलतरा में तहसील कार्यालय का चक्कर लगा-लगा कर एक व्यक्ति ने खुदकुशी की कोशिश की है।

मांगें पूरी नहीं होने से पेंशनर्स महासंघ नाराज

4 मार्च को जल संसाधन विभाग का करेंगे घेराव

रायपुर। मांगों की अनदेखी के चलते पेंशनर्स महासंघ नाराज हैं। विभागीय भविष्य निधि में जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान करने समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पेंशनर्स महासंघ 4 मार्च को जल संसाधन विभाग का घेराव करेगा। इसे लेकर राजधानी में पेंशनरों की बैठक हुई।

पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव की अध्यक्षता में बुधवार को राजधानी में बैठक हुई, जिसमें जल संसाधन विभाग की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 मार्च को प्रदर्शन करने की रणनीति पर चर्चा की गई। दैनिक वेतनभोगी सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक ने बताया कि जल संसाधन विभाग में 31 दिसंबर 1988 के पूर्व नियुक्त तृतीय व चतुर्थ वर्ग के सेवानिवृत्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों की अनदेखी की जा रही है। विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके कारण वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

ये हैं प्रमुख मांगें

दिसंबर 1988 के पूर्व से नियुक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संपूर्ण सेवा अवधि को नियमित किया जाए।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के सेवाकाल की गणना कर उपादान प्रदान किया जाए।

नियमित एवं कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को 300 दिन का अवकाश नकदीकरण भुगतान हो।

अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों का विभागीय भविष्य निधि में जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान किया जाए।

60 टी.बी मरीजों के लिए नि:क्षय मित्र बने राज्यपाल डेका

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने राज्य के धमतरी, राजनांदगांव, गरियाबंद और बस्तर जिलों के 60 टी.बी. मरीजों के लिए निक्षय मित्र बनकर उनको पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु 2 लाख 25 हजार रूपए की राशि प्रदान की है। श्री डेका ने आज उक्त राशि संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रदान की।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री टी.बी मुक्त भारत अभियान के तहत देश एवं प्रदेश को वर्ष 2025 तक टी.बी मुक्त करने का लक्ष्य है। इसके लिए जो राशि दी जा रही है उससे टी.बी मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। श्री डेका ने टी.बी मरीजों के लिए हरसंभव मदद की बात कही। उन्होंने निर्देशित किया कि राज्य को टी.बी. मुक्त बनाने के लिए समुदाय को भी जोडने का प्रयास करें।

श्री डेका ने कहा कि राजभवन आमजनता के साथ जुड़े यह हमारी प्राथमिकता है। जनता के हित के लिए अच्छा कार्य करने वाली संस्थाओं की जानकारी लेकर उन्हें स्वेच्छानुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर प्रसन्ना ने श्री डेका

को प्रधानमंत्री टी.बी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त निक्षय मित्र पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया।

इस अवसर पर राज्यपाल की संयुक्त सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, राजभवन के अन्य अधिकारी तथा संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

राज्यपाल डेका ने 15 लाख 31 हजार स्वेच्छानुदान राशि प्रदान की

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज राजभवन में अपने स्वेच्छानुदान मद से 13 संस्थाओं को 15 लाख 31 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। डेका द्वारा राजभवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल स्वेच्छानुदान मद से रैन बसेरा निर्माण, बीमार वृद्धजनों की देखभाल, दृष्टिहीन बच्चों, दिव्यांगों, वनवासियों के कल्याण के लिए कार्यरत् विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई।

राज्यपाल श्री डेका द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धमतरी को 10 टी. बी. मरीजों के लिए 50 हजार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव को 10 टी. बी. मरीजों के लिए 55 हजार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गरियाबंद को टी. बी. मरीजों के लिए 60 हजार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बस्तर को टी. बी. मरीजों के लिए 60 हजार की राशि प्रदान की गई है।

इसी तरह स्वेच्छानुदान मद से राजीव लोचन क्षेत्र स्तरीय संघ गरियाबंद को रैन बसेरा निर्माण के लिए 1 लाख, सचिव वनवासी विकास समिति रायपुर को लाइब्रेरी के लिए 5 लाख, अभिलाषा दिव्यांगजन कल्याणार्थ शिक्षण प्रशिक्षण सह पुनर्वास संस्थान राजनांदगांव को वृद्धाश्रम के लिए 2 लाख 51 हजार, वृद्धाश्रम प्रभारी एवं संरक्षक, भगवान महावीर समता वृद्धाश्रम राजनांदगांव को 1 लाख, ब्राईट शिक्षण एवं मानव कल्याण समिति %%प्रशामक देख-रेख गृह%% कादंबरी नगर दुर्ग को बीमार वृद्धों की देखभाल एवं चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख, सचिव इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, वृद्धाश्रम पुलगॉव दुर्ग को वृद्धों का देखभाल एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख, तुलसी लोक विकास संस्थान कैम्प 01 भिलाई को दृष्टिहीन बच्चों के आवासीय विद्यालय के लिए 1 लाख, श्री संदीप कुमार साहू नगर सैनिक दुर्ग को पत्नी के गले के आपरेशन के लिए 25 हजार, श्री दिनेश श्रीवास जमादार राजभवन को उनकी माता जी के कैंसर ईलाज के लिए 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर प्रसन्ना, राज्यपाल की संयुक्त सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, राजभवन के अन्य अधिकारी तथा संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस को जगाना होगा

विपिन पब्बी

यह स्पष्ट है कि किसी भी सच्चे लोकतांत्रिक देश के लिए एक प्रभावी और जिम्मेदार विपक्ष का होना आवश्यक है। दुर्भाग्य से भारत में विपक्ष पिछले एक दशक से देश को विफल कर रहा है, मुख्य रूप से अपने स्वयं के गलत कामों के कारण। हालांकि इससे भारतीय जनता पार्टी से उसकी रणनीतिक योजना और क्रियान्वयन का श्रेय नहीं छीना जाना चाहिए। शीर्ष विपक्षी नेता अंधेरे में टटोलते हुए दिखाई देते हैं और बार-बार गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर खुद को घायल कर रहे हैं। जाहिर है कि उन्होंने अतीत से सबक नहीं सीखा है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में लगातार 3 अपमानजनक हारें विपक्ष के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए थीं। हरियाणा में प्रमुख कांग्रेस को भारी जीत का इतना भरोसा था कि उसने गठबंधन सहयोगी आम आदमी पार्टी की परवाह नहीं की और अकेले ही चुनाव लडऩे का फैसला किया। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस एक प्रतिशत से भी कम वोट शेयर के साथ भाजपा से हार गई,जबकि 'आप' 1.5 प्रतिशत वोट हासिल कर सकी। अगर दोनों सहयोगी दल हाथ मिला लेते तो नतीजे काफी अलग होते। दिल्ली में 'आप' ने कांग्रेस को उसी के शब्दों में जवाब दिया और खुद को भारी नुकसान पहुंचाया तथा चुनाव हार गई। इतना ही नहीं, उसके लगभग सभी शीर्ष नेतृत्व को धूल चाटनी पड़ी। दिल्ली में भी यही कहानी दोहराई गई, जहां 'आप' को भाजपा से सिर्फ 2 प्रतिशत कम वोट मिले जबकि कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 2 प्रतिशत वोट मिले। महाराष्ट्र में भी 'इंडिया' गठबंधन ने अधिक सीटों के लिए झगड़े सहित विभिन्न कारणों से सत्ता हासिल करने का मौका गंवा दिया। उद्धव ठाकरे को उम्मीदवार घोषित न करना गठबंधन की हार का एक और कारण हो सकता है। इससे पहले गुजरात में कांग्रेस और 'आप' के बीच गठबंधन विफल होने के कारण 'आप' को 13 प्रतिशत वोट गंवाने पड़े जो कांग्रेस को मिल सकते थे। बेशक, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर विभिन्न दलों ने हाथ मिला लिया होता तो विपक्षी गठबंधन जीत जाता क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि वोट एक पार्टी से दूसरी पार्टी को सिर्फ इसलिए ट्रांसफर हो जाएं क्योंकि वे गठबंधन सहयोगी हैं। पिछले साल लोकसभा में अपनी स्थिति बेहतर करने वाली कांग्रेस हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में लगातार 3 हार के बाद फिर से अपने ही घेरे में सिमट गई है। दिल्ली में पिछले 3 चुनावों में खाता भी नहीं खोल पाने की शर्मनाक हार से उसका मनोबल जरूर टूटा होगा लेकिन पार्टी में आत्ममंथन या फिर नई जान फूंकने की कोई कोशिश नहीं दिख रही है। दूसरी ओर भाजपा को पहले से योजना बनाने और सत्ता की भूखी रहने का श्रेय दिया जाना चाहिए। उसने दिल्ली चुनाव के लिए बजट पेश किया और उसी बजट में बिहार के लिए विशेष प्रावधान किए जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। गौरतलब है कि 2020 में बिहार में हुए पिछले चुनाव में गठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया था। कांग्रेस ने अधिक सीटों पर जोर दिया था और 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन केवल 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। गठबंधन महज 12 सीटों से चुनाव हार गया था। दुर्भाग्य से विपक्षी नेता गैर-जिम्मेदाराना बयान जारी कर रहे हैं जिससे उन्हें ही नुकसान हो सकता है। कुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ करोड़ों नागरिकों की महाकुंभ में डुबकी लगाने की अपार आस्था को दर्शाती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में वयस्कों की अनुमानित संख्या 98 करोड़ है जबकि 63 करोड़ लोग पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज आए हैं। फिर भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसे 'फालतू' कहा है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा है कि यह महाकुंभ है या 'मृत्यु कुंभ'। निश्चित रूप से ऐसे बयानों से इन नेताओं की विश्वसनीयता को ही नुकसान पहुंचेगा। दिल्ली में शर्मनाक हार के बाद राहुल गांधी और उनकी मंडली 'शीतनिद्रा' में चली गई है। पार्टी बिखर चुकी है। इसे अपने घर को व्यवस्थित करने की जरूरत है। अपने केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव के अलावा पार्टी को अपनी राज्य इकाइयों को मजबूत करने और अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्त्ताओं को सक्रिय करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता की भूख के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता ताकि वह अपना एजेंडा लागू कर सके। कांग्रेस अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। अब जागने का समय आ गया है।

तमिलनाडुः 'भाषा युद्ध' और परिसीमन की पिच पर चुनावी मोर्चाबंदी

अजय बोकिल

तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। सत्तारूढ़ डीएमके ने जहां भाषा युद्ध और परिसीमन में संभावित अन्याय को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार और भाजपा पर हमले शुरू कर दिए हैं तो वहीं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके को महाभ्रष्ट सरकार बताकर उसे हटाने की दुंदुभि बजा दी है। यह साफ है कि राज्य में अब तक राजनीतिक रूप से कमजोर और हिंदुत्ववादी माने जाने वाली भाजपा ने आगामी चुनाव पूरी ताकत से लड़ने का मन बना लिया है।

ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने फिर द्रविड राजनीति की शरण ली है। उन्होंने यह धमकी देकर कि तमिलनाडु एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार है, केन्द्र सरकार और भाजपा के खिलाफ आगमी विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। स्टालिन ने चुनाव क्षेत्र परिसीमन में तमिलनाडु को होने वाले संभावित घाटे का मुद्दा उछालकर हिंदी विरोध और परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिणी राज्यों को एकजुट करने की सुनियोजित राजनीतिक कोशिशें शुरू कर दी हैं। हालांकि, हिंदी विरोध पर उन्हें ज्यादा समर्थन शायद न मिले, लेकिन परिसीमन पर स्टालिन को दक्षिणी राज्यों का साथ मिल सकता है, क्योंकि इन राज्यों का तर्क है कि चूंकि उन्होंने अपने राज्यों में जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया, इसके बदले में उन्हें संसद में कुछ सीटें गंवानी पड़ सकती हैं।

यह दक्षिण भारत की संसद में घटती आवाज का और क्षेत्रीय असंतुलन का पर्याय होगा, जो भारत जैसे संघीय राज्य में स्वीकार्य नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो देश एक और अवांछित विभाजन की ओर धकेला जा सकता है। हालांकि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में अपनी सभाओं में परिसीमन में 'अन्याय' की आशंका को पूरी तरह खारिज किया है। दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव अगले साल अप्रैल में होने वाले हैं और सत्तारूढ़ द्रविड मुन्नेत्र कडघम ने सत्ता में वापसी के लिए अभी से राजनीतिक मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। जिसमें तमिल भावनाओं को खुलकर हवा देना शामिल है। पिछले विस चुनाव में उसने अपनी चिर प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) को करारी मात दी थी, जिसका मुख्य कारण अम्मा जयललिता के

निधन के बाद एआईएडीएम का नेता विहीन होना और पार्टी की अंतर्कलह थी। एआईएडीएमके के अब दो धड़े हैं।

कुल मिलाकर यानी राज्य में विपक्ष का स्पेस खाली है। भाजपा धीरे धीरे इस स्पेस को भरने की कोशिश कर रही है। हालांकि, उसे अभी तक कोई बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिली है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत तेजी बढ़ा है। बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। जबकि डीएमके और एआईडीएमके द्रविड और तमिल अस्मिता की राजनीति करती रही हैं। हिंदी थोपने और उत्तर भारत को आर्य संस्कृति बताकर उसका विरोध द्रविड पार्टियों का प्रमुख औजार है।

दोनों पार्टियों के बीच सत्ता की अदलाबदली करिश्माई नेता के हिसाब से होती रही है। वैचारिक रूप से दोनों एक ही हैं। इस दलदल में भाजपा और आरएसएस की हिंदुत्व केन्द्रित राष्ट्रवाद की राजनीति एक अलग तासीर और आग्रह लिए हुए है, जिसका स्वीकार तमिल मानस बहुत धीरे-धीरे कर रहा है। अगले विस चुनाव में भी भाजपा को कोई बड़ी सफलता मिलेगी, यह मान लेना जल्दबाजी होगी, लेकिन उसकी राजनीतिक जमीन मजबूत हो सकती है। संभव है कि भाजपा भविष्य में सत्ता की दावेदार भी हो जाए। यही डीएमके की चिंता का मुख्य कारण है। मसलन 2020 के विस चुनाव में भाजपा को तमिलनाडु में मात्र 2.62 प्रतिशत वोट और 4 सीटें मिली थीं। यह चुनाव भाजपा ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में लड़ा था। बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके ने भाजपा से रिश्ता तोड़कर दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। लोस चुनाव में एआईएडीएमके को भी कोई सीट नहीं मिली। सीट भाजपा को भी नहीं मिली, लेकिन उसका वोट बढ़कर 18.18 प्रतिशत हो गया।

यद्यपि इस वोट प्रतिशत वृद्धि में उन छोटे का दलों का भी योगदान था, जिनसे गठबंधन कर भाजपा एनडीए के बैनर तले चुनाव में उतरी थी। जबकि इस लोस चुनाव में डीएमके गठबंधन को 46.97 फीसदी तथा मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके को 23.05 प्रतिशत वोट मिला। अपनी एकजुटता और द्रविड राजनीति के मुख्य पैरोकार के रूप में डीएमके ने राज्य में प्रतिद्वंद्वी एआईएडीएमके को काफी हद तक खत्म कर दिया है, लेकिन भाजपा को वैचारिक, जमीनी और संसाधन के स्तर पर कैसे रोका जाए, यह उसकी पहली चिंता है। यही कारण है कि एम के स्टालिन ने नई शिक्षा नीति और परिसीमन को मुद्दा बनाते हुए पोजिशनिंग शुरू कर दी है। ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में चेतावनी के स्वर में कहा कि देश में शैक्षणिक समानता के लिए सभी राज्यों को अपने यहां नई शिक्षा नीति लागू करनी होगी। तभी उन्हें केन्द्र से आर्थिक सहायता मिलेगी।

इस पर स्टालिन ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि वो राज्य के रोके गए 2152 करोड़ रू. जारी करे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु किसी हाल में अपनी द्विभाषा (तमिल और अंग्रेजी) में शिक्षा की नीति से नहीं डिगेगा। स्टालिन ने कहा कि हम भाषाई आधार पर 'ब्लैकमेल' करने का विरोध करेंगे। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार, स्कूलों में छात्रों को तीन भाषाएं सीखनी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाएं होंगी। इसका मतलब है कि राज्य की भाषा के अलावा, बच्चों को कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा सीखनी होगी ङ्क ज़रूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो। हालांकि, तमिलनाडु को आशंका है कि यह केन्द्र द्वारा हिंदी को 'पिछले दरवाजे' से थोपते हुए राज्य की भाषाई स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश है। दरअसल, त्रिभाषा नीति उसी पुराने त्रिभाषा फार्मूले का नया रूप है, जिसमें सभी राज्यों से अपने यहां बच्चों को तीन भाषा पढ़ाने की अपेक्षा की गई है। इनमें एक हिंदी अथवा स्थानीय भाषा, दूसरी अंग्रेजी तथा तीसरी कोई आधुनिक भारतीय भाषा होगी। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी भाषा किसी भी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी। देश के ज्यादातर राज्यों ने या तो नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है या फिर उस पर अपनी सहमति दे दी है। केवल तमिलनाडु ऐसा राज्य है, जिसने 1968 की पहली शिक्षा नीति को भी ठीक से लागू नहीं किया था, क्योंकि उसमें तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने की बात थी। नई शिक्षा नीति में अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को अलग से सभी स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने की बात भी है। इस पर स्टालिन का आरोप है कि संस्कृत की आड़ में तमिल भाषा का महत्व कम किया जा रहा है, जबकि तमिल भी संस्कृत जितनी ही पुरानी और सभी द्रविड भाषाओं का मूल है। उधर स्टालिन की केन्द्र को इस 'धमकी' के बाद केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसका 'उचित जवाब' दिया जाएगा। अब सवाल यह कि क्या नई शिक्षा नीति को लेकर केन्द्र और राज्य में कोई समन्वय संभव है या फिर विस चुनाव तक तो दोनो में तलवारें खिंची रहेंगी।

दरअसल, भाजपा और संघ के हिंदुत्व से सीधे सनातन पर शिफ्ट होने के पीछे भी डीएमके ही कारण थी। तमिलनाडु सरकार में उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने साल भर पहले चेन्नई में एक प्रायोजित कार्यक्रम में हिंदू धर्म की मुख्य धारा सनातन को 'बीमारी' की संज्ञा दी थी। इसके बाद भाजपा और संघ के सनातन को अपने प्रचार का मुख्य हथियार बना लिया। इसका उसे चुनावों में फायदा भी मिला।

हिंदी को लेकर तमिलनाडु का विरोध 1937 से है। वह देश में अकेला ऐसा राज्य है, जहां स्कूलों में राजभाषा और अघोषित रूप से राष्ट्रभाषा का स्वरूप ले रही हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। इससे नुकसान उन बच्चों का होता है, तो तमिलनाडु के बाहर अन्य राज्यों में नौकरी धंधा करना चाहते हैं। नतीजा यह है कि विद्यार्थी निजी स्तर पर हिदी सीख रहे हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी परीक्षा में तमिल विद्यार्थियो की बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है।

इसका सीधा अर्थ यही है कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध मुख्यत: राजनीतिक है और द्रविड राजनीति की प्रासंगिकता को कायम रखने की एक प्रभावी आड़ है। जबकि बीती आधी सदी में काफी कुछ बदल चुका है। स्टालिन का दूसरा मुद्दा ज्यादा गंभीर और विचारणीय है। इस साल देश में 16 वीं जनगणना होना संभावित है। साथ ही अगले साल 2026 में संसदीय व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का देश की बढ़ती आबादी के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से परिसीमन होना है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

कल्पना कीजिए कि आपकी सम्मति में ब्रह्मा दुहिता वाली कथा में ब्रह्मलोक में अधिष्ठाता, सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी महाराज अभिप्रेत हैं। यहां सूर्य उषा और मन:वाणी-परक आधिभौतिक और आध्यात्मिक अर्थ नहीं करने चाहियें । इससे जहाँ एक अंश की पुष्टि होगी, वहां दो अंशों का चकनाचूर भी तो हो जायगा, क्योंकि वेद (ऋग्वेद 8 । 1 । 27) ब्राह्मण (शतपथ 1।7।4।1) और कुमारिल भट्ट ने तन्त्र-वार्तिक 1।3।7 में इसे सूर्य-उषा परक कथन किया है।

ब्रह्मवैवर्तपुराण (4।36।58) में स्वयं व्यासजी इसे मन:-वाणी-परक कह रहे हैं। ऐसी अवस्था में किसी एक पक्ष को मानकर शेष पक्षों की अवहेलना नहीं की जा सकती। इसलिये हम तो स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि न तोथियासोफिकल सोसायटी के मतानुसार पुराणों को केवल रूपकालङ्कार के साँचे में डालना चाहिए, और नांही दूसरे सम्प्रदाय की सम्मत्यनुसार केवल आधिदैविक अर्थ को मान कर शेष अर्थों की अवहेलना करनी चाहिए। किन्तु यथासम्भव आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक एवं ऐतिहासिक सभी प्रकार के अर्थ ठीक और सत्य मानने चाहिएं। अधिकारी भेद से जिसे जो रुचिकर हो वह उसे ग्रहण कर सकता है। एक कथा के कई 2 अर्थ होना, यह पुराणों के लिए दूषण नहीं, किन्तु भूषण है। जैसे वेदों में एक ही मन्त्र कई स्थानों में आता है, परन्तु ग्रार्षसिद्धान्तानुसार इसे पुनरुवत दोष नहीं कहा जा सकता, किन्तु वह मन्त्र प्रसङ्गानुसार प्रर्थभेद से कई कार्यों में विनियुक्त माना जाता है। इसोप्रकार पुराणों की कथाएं भी अधिकारी-भेद से यथायोग्य अर्थों वाली हैं। चन्द्र तारा की कथा का जहाँ एक ओर खगोल-विषयक अर्थ होता है वहाँ चन्द्रवंश की उत्पत्ति से भी उसका सम्बन्ध है।

क्रमश: ...

डॉ राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, जो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनें

अनन्या मिश्रा

स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉ राजेन्द्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने आरत की आजादी में अपना अहम योगदान दिया था। बता दें कि वह बिहार के मुख्य नेता थे। वहीं नमक छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉ, राजेंद्र प्रसाद को काफी यातनाएं भी झेलनी पड़ी थी। वहीं भारतीय संविधान के निर्माण में उनका अहम योगदान था। आज ही के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति और भारत के महान स्वतंत्रा सेनानी का निधन हुआ था।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई (बिहार) में हुआ था। सादगी पसंद, दयालु एवं निर्मल स्वभाव के व्यक्ति थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम महादेव सहाय था। उनके पिता फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। उनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। बचपन में अपने जन्मस्थान से शुरूआती शिक्षा के दौरान उन्होंने फारसी, उर्दू, हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए छपरा और फिर पटना गए। जहां पर उन्होंने कानून में मास्टर की डिग्री के साथ डॉक्टरेट भी किया। कानून की पढ़ाई के दौरान वह राष्ट्रीय कांग्रेस में भी शामिल हुए थे।

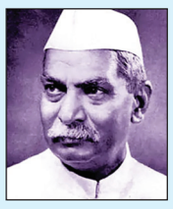

डॉ. राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं महात्मा गांधी ने उनको अपने सहयोगी के तौर पर चुना था। इसी के साथ गांधी जी ने उन पर साबरमती आश्रम की तर्ज पर सदाकत आश्रम की एक नई प्रयोगशाला का दायित्व सौंपा था। ब्रिटिश प्रशासन ने राजेंद्र प्रसाद को नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में डालकर कई तरह की यातनाएं दी थीं।

आपको बता दें कि डॉ राजेंद्र प्रसाद साहित्य-संस्कृति, शिक्षा, इतिहास, धर्म, वेदांत, राजनीति, भाषा आदि विषयों पर वह अपने विचार व्यक्त करने से पीछे नहीं हटते थे। स्वाभाविक सरलता के कारण उन्होंने कभी भी अपने प्रभाव को प्रतिष्ठित करने का प्रयास नहीं किया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद सादा जीवन-उच्च विचार के सिद्धांत को अपना कर चलने वाले व्यक्ति थे। वह सभी से काफी नम्रता से बात करते थे। उनकी यही प्रतिभा उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी।

देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिला। इसके साथ ही डॉ राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रा भारत के पहले राष्ट्रपति बने। वर्ष 1957 में वह दोबारा राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए। बता दें कि डॉ राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, जो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनें। डॉ. राजेंद्र प्रसाद को राजनैतिक और सामाजिक योगदान के लिए साल 1962 में भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान के तौर पर भारत रत्न से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने अपने राजनैतिक सफर पर विराम लगाते हुए संन्यास ले लिया। बता दें कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अपना आखिरी समय पटना के एक आश्रम में बिताया था। बीमारी के चलते 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया।

यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका-रूस एक साथ

अनिल त्रिगुणायत

संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन युद्ध खत्म करने के मुद्दे पर अमेरिका और रूस का एक साथ आना निश्चय ही बहुत आश्चर्यजनक है। जिन लोगों को शीतयुद्ध की याद है, वे मानेंगे कि दोनों देशों के संबंधों में बड़ा बदलाव आया है। लेकिन मेरा मानना है कि दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। उनका रवैया निरंतरता की ओर ही अग्रसर है। ट्रंप शुरू से ही रूस के साथ बेहतर संबंध बनाये रखने के पक्षधर थे। पहले राष्ट्रपति काल में भी उन्होंने पुतिन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की थी। लेकिन तब अमेरिकी डीप स्टेट के कारण वह ऐसा नहीं कर पाये थे। दूसरे राष्ट्रपति काल में ट्रंप ने मस्क की मदद से अमेरिकी डीप स्टेट को खत्म करना शुरू किया है। ऐसे में रूस के साथ बेहतर संबंध बनाने में उन्हें शायद ही मुश्किल आये।

अमेरिका और रूस के साथ यूरोप के मौजूदा रिश्ते को देखें, तो भी अजीब विरोधाभास दिखता है। शीतयुद्ध के दौर में पश्चिमी यूरोप की प्रभावशाली कम्युनिस्ट पार्टियों के तत्कालीन सोवियत संघ से गहरे रिश्ते थे, और अमेरिका इनके विरोधियों को आर्थिक और राजनीतिक मदद देता था। आज यूरोप में दक्षिणपंथ का उभार है, और अमेरिका उससे अलग कम्युनिस्ट रूस के नजदीक जा रहा है। इसका प्रभाव अमेरिका और यूरोप के रिश्ते में आये खिंचाव में तो दिख ही रहा है, इसका असर यूक्रेन युद्ध के खात्मे पर भी पड़ेगा। यूरोप के देश यूक्रेन के साथ हैं, और वे चाहते हैं कि इस युद्ध का अंत होने का मतलब यूक्रेन का आत्मसमर्पण और उसकी संप्रभुता से समझौता नहीं होना चाहिए।

अलबत्ता यह देखने वाली बात होगी कि यूक्रेन युद्ध के खात्मे में यूरोप की भूमिका ज्यादा होगी या फिर अमेरिका-रूस की चलेगी। ट्रंप से व्हाइट हाउस

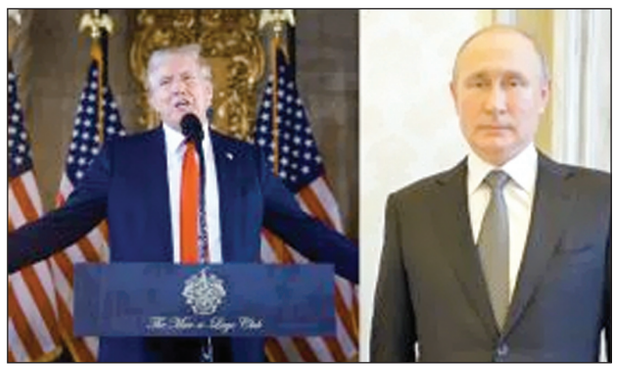

में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की मुलाकात के दौरान भी यूक्रेन मुद्दे पर पैदा खिंचाव का असर दिखा, लेकिन अच्छी बात यह रही कि दोनों ने शांति बहाली की बात की। गौरतलब है कि ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे मिलने वाले पहले यूरोपीय नेता मैक्रों ही हैं। जो लोग यह समझ रहे हैं कि पुतिन के करीब जाकर ट्रंप अपने देश के लिए बेहतर करने की कोशिश में हैं और इससे यूक्रेन युद्ध का मसला हल नहीं होने वाला, वे गलत सोचते हैं। अव्वल तो अमेरिका और रूस का करीब होना ही वैश्विक परिदृश्य में एक बड़ी घटना है। कहने को यह भी कहा जा सकता है कि रूस अब पहले जैसी शक्ति नहीं रहा, जो यूक्रेन युद्ध में भी भलीभांति दिखाई पड़ा। इन तीन वर्षों के दौरान रूस की सैन्य शक्ति और उसकी अर्थव्यवस्था और खराब हुई है। ऐसे में, रूस से शत्रुता निभाना या प्रतिद्वंद्विता रखना अमेरिका के लिए बुद्धिमानी नहीं है।

अमेरिका के लिए रूस से भी ज्यादा मुश्किल देश आज के दौर में चीन है। दरअसल रूस और चीन का एक साथ होना भी अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत का कारण रहा है। ऐसे में, रूस के साथ मिलकर अमेरिका अगर अपने प्रतिद्वंद्वी चीन को कुछ कमजोर या अलग-थलग कर सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। इससे ट्रंप की एक बड़ी चिंता दूर हो जायेगी। ट्रंप के रूस प्रेम का यह बड़ा कारण है। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि पुतिन का वास्तविक इरादा दरअसल उस नाटो को विस्तार करने से रोकना है, जो कभी यूरोपीय देशों को सोवियत संघ से बचाने के लिए बना था। आज स्थिति यह है कि नाटो का विस्तार रूस के बगल तक हो चुका है और पुतिन की चिंता का यही सबसे बड़ा कारण है। चूंकि ट्रंप अमेरिका को किसी भी वैश्विक संगठन में बनाये रखने के विरोधी हैं, ऐसे में, पुतिन को यह लगता होगा कि ट्रंप को अपने साथ लेकर वह नाटो के असर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अभी तो यह दूर की कौड़ी है, और यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई में बहुत कुछ खो चुके पुतिन फिलहाल बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश में शायद ही होंगे।

अभी तो अमेरिका-रूस का एक साथ होना यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की दिशा में भी उम्मीद की तरह है। ट्रंप के रवैये से सरसरी तौर पर यह लगता है कि वह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को खलनायक की तरह देखते हैं। उन्होंने जेलेंस्की को तानाशाह कहा भी है। खुद जेलेंस्की की राय भी ट्रंप के प्रति अच्छी नहीं है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में आप दो अमेरिकी राष्ट्रपतियों- जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को देखें, तो अंतर साफ-साफ दिखाई देता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को भारी मदद दी। यह युद्ध अगर इतने दिनों तक जारी है और यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके, तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अमेरिकी मदद का रहा। दूसरी ओर, ट्रंप इस युद्ध में यूक्रेन की मदद नहीं करने वाले। बल्कि दुनिया के किसी भी इलाके में होने वाले युद्ध में अमेरिका मदद नहीं करेगा।

आलोचकों के एक वर्ग का कहना है कि दुनिया में शांति बनाये रखने की अपनी जिम्मेदारी से अमेरिका मुंह मोड़ रहा है। बेशक अमेरिका से बाहर हस्तक्षेप न करने की ट्रंप की नीति अमेरिकी स्वार्थ से जुड़ी है। ट्रंप के राष्ट्रपति काल में अमेरिका का पैसा सिर्फ अमेरिका की बेहतरी में खर्च होगा। अमेरिका बाहर कहीं हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो इससे युद्ध और अशांति की आशंकाएं बढ़ेंगी नहीं, घटेंगी। ट्रंप यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की की मदद नहीं करेंगे, तो यूक्रेन युद्ध जल्दी खत्म होगा। सिर्फ एक बात की गारंटी नहीं दे सकते। यह नहीं कह सकते कि यह युद्ध कब खत्म होगा और इसकी कीमत क्या होगी। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जिस युद्ध के तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं, और जो तीसरे विश्वयुद्ध की शक्ल अख्तियार कर सकता था, उसके खत्म होने की संभावना ही बड़ी बात है।

हाल ही में यूक्रेन में पाये जाने वाले खनिजों के मामले में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो सहमति बनी है, उससे भी दो बातें साफ होती हैं। एक यह कि ट्रंप-जेलेंस्की के रिश्ते उतने शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, जितना कि बताया जा रहा है। अगर उनके आपसी संबंध तनावपूर्ण होते, तो जेलेंस्की के सामने अमेरिका से समझौता करने की क्या मजबूरी थी? जाहिर है कि दोनों के बीच एक स्तर पर समझदारी बनी हुई है। फिर खनिज समझौते से यह भी साफ हो जाता है कि यूक्रेन को आने वाले दिनों में रूस के हमले से बचाने के बदले ट्रंप जेलेंस्की से यह कीमत वसूल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के प्रस्ताव पर चीन और भारत ने वोटिंग न कर तटस्थता का संदेश दिया। लेकिन कुल मिलाकर देखें, तो बदल रहा वैश्विक परिदृश्य और यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की उम्मीद भारत के लिए भी उतनी ही संभावनापूर्ण है, क्योंकि भारत शुरू से ही अपने आपको निष्पक्ष और शांति का पक्षधर बताता रहा है।

आज का इतिहास

1850 यूटा विश्वविद्यालय साल्ट लेक सिटी यूटा में खोला गया।
1854 रिक में औपचारिक रूप से रिपब्लिकन पार्टी का आयोजन किया गया।
1861 कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया।
1874 एक अंग्रेजी अदालत में अब तक के सबसे लंबे मामलों में से एक में, प्रतिवादी को टीकबॉर्न बैरनेटरी के वारिस की पहचान का प्रयास करने के लिए पर्ज के दोषी ठहराया गया था।
1897 रानावलोना III, मेडागास्कर के अंतिम शासक शासक, एक फ्रांसीसी सैन्य बल द्वारा हटा दिया गया था।
1908 इटली के मेसिना में भूकंप से करीब 80 लोग मारे गये।
1914 बाल्कन युद्धों के बाद, दक्षिणीअलबीनिया में रहने वाले यूनानियों ने ऑटोनॉमस रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न एपिरस घोषित किया।
1935 रासायनिक कंपनी ड्यूपॉन्ट के लिए एक नया व्यवहार्य फाइबर विकसित करने के लिए पॉलियामाइड्स के साथ काम करते हुए, अमेरिकी रसायनज्ञ वालेस कैरोज़र्स ने नायलॉन का आविष्कार किया।
1942 रॉबर्ट सुलिवन पहले पायलट बने, जिन्होंने अटलांटिक महासागर के ऊपर एक सौ बार उड़ानें भरी।
1950 द पीक डिस्ट्रिक्ट ब्रिटेन का पहला राष्ट्रीय पार्क बना।
1972 जापानी पुलिस ने अर्धसैनिक समूह युनाइटेड रेड आर्मी के सदस्यों द्वारा दस दिन की घेराबंदी को समाप्त करने के लिए, करुनिजावा, नागानोप्रेक्कर के पास एक पहाड़ लॉज पर हमला किया।
1972 अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की पीपुल्स रिपब्लिक चीन यात्रा दोनों देशों के साथ संपन्न हुई, जिसमें शंघाईकोमुनिके जारी किया गया, जो पूर्ण-सामान्य संबंधों की दिशा में काम करने का वचन देता है।
1974 पाकिस्तान में 6.3 तीव्रता के भूकंप में 5200 मरे गए।
1985 द ट्रॉबल्स-द प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने उत्तरी आयरलैंड के कोरी स्क्वायर, रॉयल में एक यूलस्टर कांस्टेबुलरी स्टेशन पर नौ हमले की शुरुआत करते हुए हमला किया।
1986 स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे की हत्या स्टॉकहोम में एक अकेला बंदूकधारी ने की थी, जब वह अपनी पत्नी लिस्बेट पाल्मे के साथ फिल्म थियेटर से घर लौट रहे थे।

महाकुंभ की ऐतिहासिक सफलता पर अनर्गल प्रलाप क्यों?

ललित गर्ग

महाकुंभ केवल एक धार्मिक समागम ही नहीं है, यह भारत की संस्कृति का भी परिचायक एवं आत्मा है। इस बार महाकुंभ में जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, वह अकल्पनीय है, विश्व में इतने विशाल जनसमूह को आकर्षित एवं नियोजित करने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इस सफल एवं ऐतिहासिक आयोजन से विपक्षी दल एवं नेता बौखलाये हुए हैं और अपने बेतूके एवं अनर्गल प्रलाप से न केवल इस आयोजन की सफलता-गरिमा को धुंधलाना चाहते हैं बल्कि सनातन संस्कृति का उपहास उड़ा रहे है। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने महाकुम्भ को मृत्युकुम्भ कहा तो सपा सांसद जया बच्चन एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कहते हैं कि शवों को गंगा में बहा दिया गया, लालू यादव कहते हैं फालतू है महाकुम्भ। इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए हैं। ऐसे एवं कुछ अन्य विपक्षी नेताओं के भ्रामक, त्रासद एवं गुमराह करने वाले बयानों से वहां जाने वाले लोगों को भयभीत, आतंकित और आशंकित किया गया। इन विपक्षी नेताओं का एक वर्ग, धर्म का मखौल एवं उपहास उड़ाते हुए लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती हैं। यह समझ आता है कि कुछ तथाकथित प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्षतावादी लोगों को सनातन धर्म से जुड़ा हर पर्व और परंपरा रास नहीं आती, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वे अन्य मतावलंबियों के ऐसे धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों पर उसी तरह की टीका टिप्पणी करते हैं जैसी उन्होंने महाकुंभ को लेकर की। आखिर हिन्दू समाज अपने अस्तित्व एवं अस्मिता पर हो रहे इन हमलों एवं आघातों के लिये कब जागरूक एवं संगठित होगा?

प्रयागराज महाकुंभ 2001, इस सहस्राब्दी का पहला कुंभ था, जो एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के चलते 144 साल बाद हुआ है। जिसमें लगभग 62 करोड़ से अधिक लोगों के स्नान, रहने, चिकित्सा, यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और सुरक्षा की शानदार एवं ऐतिहासिक व्यवस्थाएं करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने न केवल देश बल्कि दुनिया को चौंकाया है। यह दुनिया का पहला विशाल आयोजन है, जिससे भारत एवं सनातन धर्म का गर्व एवं गौरव दुनिया में बढ़ा है। बावजूद इसके विपक्षी नेता जिस तरह की बातें कह एवं कर रहे हैं, निश्चित ही यह उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता, सनातन विरोधी मानसिकता को ही दर्शा रहा है, वे लगातार विभाजनकारी राजनीति को प्रोत्साहन देते हुए भूल जाते हैं कि उनके ऊपर देश को तोड़ने नहीं, जोड़ने की जिम्मेदारी है। वे जानते नहीं कि वे क्या कह रहे हैं। उससे क्या नफा-नुकसान हो रहा है या हो सकता है। वे तो इसलिए बोल रहे हैं कि वे बोल सकते हैं, उन्हें बोलने की आजादी है, लेकिन इसका नुकसान देश को भुगतना पड़ रहा है। विडम्बना देखिये कि इसका नुकसान उनको एवं उनके दल को भी हो रहा है। भारत में सनातन विरोध की राजनीति करके वे अपनी ही जड़े उखाड़ रहे हैं, यह उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को ही दर्शा रहा है।

मध्यप्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम मेडिकल एवं साइंस रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाकुंभ का उल्लेख करते हुए जिस तरह कुछ विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा, उसकी आवश्यकता इसलिए थी, क्योंकि कुछ लोग वास्तव में अनावश्यक और अनर्गल टीका-टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। पुरानी कहावत है, मियाँ को न पाऊँ तो बीवी को नोच खाऊँ वाली स्थिति विपक्षी नेताओं एवं दलों की हो

चुकी है। इसे छिद्रान्वेषी मानसिकता ही कहा जाएगा। इस प्रकार की उद्देश्यहीन, अनर्गल, उच्छृंखल एवं विध्वंसात्मक आलोचना से किसी का हित सधता हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। विपक्षी नेता अपने नजरिए को बदलें और देश में नफरत और झूठ की राजनीति करके भ्रम फैलाने की ओछी राजनीतिक हरकतों से बाज आएं। विपक्ष जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, वह किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती। विपक्षी नेताओं ने सारी हदें लांघते हुए जो तुलनाएँ की, जो अनर्गल प्रलाप किया है वह निश्चित रूप से अतिरेक या अतिशयोक्ति कही जा सकती हैं। प्रतीत होता है हर दिखते समर्पण की पीठ पर स्वार्थ चढ़ा हुआ है। इसी प्रकार हर अभिव्यक्ति में कहीं न कहीं स्वार्थ की राजनीति है, सत्तापक्ष को नुकसान पहुंचाने की ओछी मनोवृत्ति है।

कुछ विपक्षी नेताओं ने चुन-चुनकर इस आयोजन की समस्याओं को गिनाने में अतिरिक्त दिलचस्पी दिखाई और इस क्रम में वहां मची भगदड़ का जिक्र करते हुए यहां तक कहा कि उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। यह गैरजिम्मेदारी, मानसिक दिवालियापन एवं अपरिपक्व सोच के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को कठघरे में खड़ा किया, क्योंकि वे हिंदू आस्था पर जानबूझकर प्रहार ही कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने सही कहा कि महाकुंभ भारत की संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। यह ठीक है कि जिस आयोजन में प्रतिदिन एक-दो करोड़ लोगों की भागीदारी होती हो, वहां कुछ समस्याएं हो सकती हैं और वे दिखीं भी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इस आयोजन को विफल बताने की कोशिश की जाए अथवा यह कहा जाए कि श्रद्धालुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। अच्छा हो कि विपक्षी नेता यह समझें कि ऐसे आयोजनों पर उनकी बेजा एवं बेतूकी टिप्पणियां उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान ही पहुंचाती हैं।

हिन्दू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी शक्ल में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे ये लोग हिन्दू मठों, मंदिरों, संतों, संस्कृति व सिद्धांतों पर हमला करते हुए राजनीति करते रहे हैं। ऐसे लोग भूल जाते है कि हिन्दू भारत का बहुसंख्य वर्ग है, भारत एक हिन्दू राष्ट्र है, उसका विरोध करते हुए वे अपनी राजनीति जमीन को ही खोखला करते हैं। मोदी-योगी एवं भाजपा विरोध करते हुए वे राष्ट्र एवं सनातन विरोध पर उतर आते हैं। हिन्दू पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते है, जो धर्म एवं संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, विश्व मानवता को जोड़ने वाली है, उस पर कीचड़ उछाल कर वे सछिद्र नाव में सवार है। हिन्दू समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा हैं।

महाकुम्भ कोई नया आयोजन नहीं है, बल्कि यह वैदिक परंपरा से चला आ रहा है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और श्रीमद्भागवत महापुराण में भी इसका उल्लेख है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति की आत्मा है और इसे संकीर्ण राजनीतिक नजरिए से देखना अनुचित है। विपक्षी दलों के बयान ना सिर्फ़ उनके सनातन विरोधी चरित्र को दिखाता हैं बल्कि उनकी गिद्धदृष्टि को भी उजागर करता है जो महाकुंभ के खिलाफ़ दुष्प्रचार की आंधी से हिन्दू धर्म एवं संस्कृति को धुंधलाने की कुचेष्टा एवं षडयंत्र है। यह सनातन धर्म पर प्रहार न केवल निंदनीय है बल्कि शर्मनाक भी है। जबकि विदेशों से आये मेहमानों ने महाकुंभ के भव्य, व्यवस्थित एवं सफल आयोजन की भरपूर सराहना की है, इटली से आए एक श्रद्धालु ने कहा, यहां आकर जो मेरा अनुभव है, वह काफी शानदार रहा है। इटली के ही एक फोटोग्राफर ने कहा कि वह महाकुंभ की तस्वीरें लेने आए हैं। कुंभ में घूमने के दौरान कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला। मुझे भारत की विविधता काफी अच्छी लगती है। उन्होंने बताया कि वह अब तक पांच कुंभ मेलों में शामिल हो चुके हैं, लेकिन यह उनमें सबसे बेहतर है। ब्रिटेन से आई एक श्रद्धालु ने कहा, बहुत खुश हूं। यह एक बहुत ही खास जगह है। यह काफी जादुई लगता है। बहुत, बहुत अच्छा, एक प्यारा अनुभव। ब्रिटेन के ही एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि यहां गंगा नदी में स्नान का अनुभव काफी अच्छा है। मैं समझता हूं कि भारत सबसे बढ़िया देश है। इस तरह भारत के गौरव को बढ़ाने वाली इन टिप्पणियों से न केवल महाकुंभ बल्कि सनातन संस्कृति का दुनिया में परचम फहराया है बल्कि उसमें चार चांद लगे हैं।

चुनावी राजनीति में 'बी' टीम होने के आरोपों का क्या है सच?

राजकुमार सिंह

आम आदमी पार्टी के दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने से संतुष्ट कांग्रेस ने अब बसपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अब मायावती की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाते हुए बसपा को भाजपा की 'बी' टीम बताने की कोशिश की है। आप और कांग्रेस के बदलते रिश्ते किसी से छिपे नहीं। आप ने कांग्रेस से दिल्ली और पंजाब की सत्ता तो छीनी ही, गुजरात और गोवा समेत कुछ अन्य राज्यों में भी उसे नुकसान पहुंचाया। फिर भी राष्ट्रीय राजनीति में मोदी की भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस और आप, 'इंडिया' गठबंधन में साथ आ गए।

लेकिन जब केंद्रीय सत्ता का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो दिल्ली में आप को हराने के उद्देश्य के साथ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ताल ठोंक दी। पिछली बार साढ़े चार प्रतिशत से कम मत पानेवाली कांग्रेस 2।8 प्रतिशत मत बढ़ा कर भी लगातार तीसरी बार खाता नहीं खोल पाई, लेकिन कम-से-कम 14 सीटों पर आप को हरवा दिया।

अतीत में आप ने जो भूमिका निभाई, वही इस बार दिल्ली में कांग्रेस ने निभाई। तब आप को भाजपा की 'बी' टीम कहा गया, अब कांग्रेस को क्या कहा जाए? चुनावी मुकाबले में तीसरे खिलाड़ी पहले भी बाजी पलटते रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा में तो आप की चुनावी मौजूदगी बहुत स्पष्ट नजर आई, लेकिन हरियाणा में भी उसकी भूमिका नजरअंदाज नहीं की जा सकती। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बमुश्किल एक प्रतिशत मत ज्यादा पा कर भाजपा वहां भी सत्ता की 'हैट्रिक' में सफल हो गई। बेशक इनेलो-बसपा और जजपा-आसपा जैसे गठबंधनों ने चुनाव को बहुकोणीय बना दिया था, लेकिन कांग्रेस-आप साथ होते तो परिणाम बदल भी

सकता था। अब राहुल गांधी द्वारा बसपा पर टिप्पणी को समझते हैं। अतीत में बसपा से चुनावी गठबंधन कर चुकी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दलित राजनीति में कांशीराम और मायावती के योगदान की प्रशंसा करते हुए टिप्पणी की कि अब बहन जी सरकारात्मक ढंग से चुनाव नहीं लड़तीं।

उन्होंने कहा कि अगर बसपा, 'इंडिया' गठबंधन के साथ होती तो भाजपा नहीं जीत पाती। जाहिर है, वह पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जिनमें 'इंडिया' गठबंधन के चलते भाजपा 303 से घटकर 240 सीटों पर आ गई। उत्तर प्रदेश ने पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा को बहुमत दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई और लगातार दूसरी बार राज्य में उसकी सरकार भी बनाई। पर लोकसभा चुनाव में जोरदार झटका दे दिया। इसीलिए राहुल कह रहे हैं कि बसपा भी साथ होती तो भाजपा हार जाती। मामला चुनावी रणनीति के अलावा वोट बैंक का भी है। आप ने कांग्रेस के परंपरागत गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाकर नुकसान पहुंचाया तो उसने वापस पाने की कवायद में इस बार दिल्ली में हिसाब बराबर कर लिया।

कांग्रेस और बसपा के बीच तल्खी के मूल में दलित वोट बैंक भी है। बसपा से पहले दलित, कांग्रेस का वोट बैंक रहे। उत्तर प्रदेश और पंजाब में बड़ी संख्या में होने के अलावा शेष देश में भी दलित वोट बैंक की चुनावी राजनीति में प्रभावशाली भूमिका है। कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर है, जिसमें मायावती की अबूझ राजनीति के चलते बिखराव दिख रहा है।

एक नई कूटनीतिक संस्कृति का दौर शुरू?

हरीश गुप्ता

कूटनीतिक हलकों में इस बात को लेकर काफी आश्चर्य है कि राष्ट्रपति ट्रम्प की एमएजीए (मागा) टीम के प्रमुख एलन मस्क भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर, अजित डोभाल व अन्य शीर्ष अधिकारियों से बने उनके उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करके किस तरह का संदेश देना चाहते थे। वाशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस गए प्रतिनिधिमंडल को आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने पाया कि मस्क के साथ उनके सलाहकार और पत्नी, तीन बच्चे और उनकी नैनी भी थे।

बेशक, मोदी की मस्क के साथ अच्छी बैठक हुई, लेकिन इसने गंभीरता की कमी का संकेत भी दिया। हालांकि कई लोग कहते हैं कि यह यूएसए में विकसित हो रही एक नई संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन कई लोग इस परिवर्तन से खुश नहीं हैं और सोचते हैं कि एक उचित कूटनीतिक संरचित बैठक और प्रक्रिया होनी चाहिए थी। लेकिन कूटनीति के खेल में ट्रम्प और मस्क अलग-अलग तरह के खिलाड़ी हैं।

कूटनीतिक हलकों का कहना है कि दिखावे के लिहाज से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच शिखर बैठक में भी केवल एक रोडमैप पेश किया गया, जिसमें भारत द्वारा टैरिफ में और कटौती, तेल और गैस की खरीद में वृद्धि और अमेरिका के पांचवीं पीढ़ी के एफ-35 विमानों की संभावित खरीद शामिल थी। लेकिन यह दोनों के लिए एक शानदार पल था, क्योंकि ट्रम्प ने मोदी को 'मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त' कहा, और दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया। यह अलग बात है कि ट्रम्प ने भारत सहित अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों पर 'पारस्परिक' टैरिफ की धमकी देने से कुछ

घंटे पहले ही एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। चूंकि मोदी यह शिखर सम्मेलन चाहते थे, इसलिए अमेरिका ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने एस। जयशंकर के प्रयासों की बदौलत मोदी की यात्रा को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ऐसा कहा जाता है कि ट्रम्प किसी बात को लेकर मोदी से नाराज हैं, हालांकि सब कुछ ठीक लग रहा था, सिवाय इसके कि ट्रम्प व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस से मोदी को रिसीव करने के लिए बाहर नहीं आए। दिलचस्प बात यह है कि ट्रम्प ने मोदी के भारत आने के निमंत्रण का तुरंत जवाब भी नहीं दिया। पिछले कुछ समय से भाजपा राजधानी और अन्य जगहों पर धीरे-धीरे सभी प्रमुख स्वतंत्र संस्थानों और क्लबों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। ये लंबे समय से या तो कांग्रेस या तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादियों के अधीन थे। लेकिन 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद चीजें बदल गईं।

भाजपा नेताओं ने दिल्ली गोल्फ क्लब पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यह कदम इसलिए टाल दिया क्योंकि यह बहुत मुश्किल था और सही समय का इंतजार करने का फैसला किया गया। लेकिन दिल्ली जिमखाना क्लब में वे सफल रहे क्योंकि प्रबंध समिति में अंदरूनी लड़ाई चल रही थी।

पहले, सुरक्षा के नाम पर इसे बंद करने के बारे में सोचा गया था क्योंकि यह प्रधानमंत्री के आवास के बहुत करीब है और इसलिए इसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए। लेकिन नौकरशाहों ने इस पर आपत्ति जताई और जल्द ही एक रास्ता निकाल लिया गया। अब, सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब का प्रशासक नियुक्त किया है जो इसे चलाता है। समिति को भंग कर दिया गया है। इसी तरह इंडिया हैबिटेट सेंटर अनुभवी पूर्व राजनयिक भास्वती मुखर्जी के अधीन है। वह भाजपा की करीबी सहयोगी और एक पेशेवर हैं और अब इंडिया हैबिटेट सेंटर की अध्यक्ष हैं। अब इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की बारी है। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने आईआईसी के न्यासी बोर्ड के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है।

बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर मिश्रा जीतते हैं तो भाजपा आईआईसी पर कब्जा कर लेगी जो दशकों से वामपंथियों का गढ़ रहा है। लेकिन कोई भी सुनिश्चित नहीं है क्योंकि कोई और उम्मीदवार खड़ा हो सकता है और मुकाबले की स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा जीतती है या यह पिछले कई दशकों से आईआईसी पर पारंपरिक रूप से काबिज लोगों के पास चली जाती है। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भले ही हिम्मत दिखा रहे हों और तरह-तरह के बयान दे रहे हों, लेकिन घर के अंदर उनका चेहरा उदास और हताश है। वे अपना आपा खो रहे हैं और खुद को दोराहे पर खड़ा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शीश महल खाली करने के बाद वे नए सरकारी घर में शिफ्ट नहीं हुए। बल्कि उन्होंने अपने एक राज्यसभा सांसद से फिरोजशाह रोड स्थित घर खाली करने को कहा, ताकि वे वहीं रह सकें। बताया जाता है कि केजरीवाल ने दिल्ली से मौजूदा राज्यसभा सांसद एन.डी। गुप्ता से बंगला खाली करने को कहा, ताकि वे अपने परिवार के साथ वहां रह सकें।

गुप्ता ने स्वाति मालीवाल की तरह व्यवहार करने के बजाय ऐसा करने में कोई देरी नहीं की और अपने मालिक की बात मान ली। सवाल यह है कि सांसदों के बंगलों से संबंधित नियमों के तहत इस तरह का बंटवारा या सब-लेटिंग जायज है या नहीं। लालफीताशाही को कम करने की मोदी की योजना धराशायी हो गई क्योंकि नए कैबिनेट सचिव ने पाया कि उनके पूर्ववर्ती राजीव गौबा के नोट को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में उनके अधीन काम करने वाले सचिवों ने नजरअंदाज कर दिया था, जिसमें उन्हें निर्णय लेने वाले स्तरों के चार से अधिक नहीं होने के लिए कहा गया था। टीवी सोमनाथन निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी से बेहद परेशान हैं। उन्हें मंत्रालयों को निर्दिष्ट करने वाला दो साल पुराना आदेश मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यह बताए जाने के बाद कि भारत आसानी से व्यापार करने के लिए एक कठिन जगह है, इस मामले ने तत्काल तूल पकड़ लिया। सभी मंत्रालयों को पिछले आदेश का पालन करने के लिए सख्त संदेश भेजा गया है।

विदेश मंत्रियों की चर्चा से खुली कैलाश मानसरोवर यात्रा की राह

उमेश चतुर्वेदी

दक्षिणी अफ्रीकी शहर जोहान्सबर्ग में यूं तो जी 20 के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। इसमें अलग हटकर अगर एशिया के दो महत्वपूर्ण, ताकतवर और पड़ोसी देशों चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी तो उस पर कूटनीतिक हलकों की नजर जाना स्वाभाविक है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात को दोनों ही देशों में उम्मीद से देखा जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों के साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर सार्थक चर्चा की है। इसका असर इसी साल की गर्मियों में दिखेगा, जब भारतीय श्रद्धालु कैलाश-मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे। यहां ध्यान देने की बात यह है कि जब से दोनों देशों के आपसी रिश्तों में असहजता आई थी, तब से कैलाश-मानसरोवर यात्रा रूकी हुई है। इस यात्रा के शुरू होने के गहरे मायने हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय श्रद्धालु अपने तीर्थ स्थल की यात्रा ही नहीं करेंगे, वैश्विक स्तर पर सौहार्द का संदेश भी लेकर जाएंगे।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भारतीय विदेश मंत्री की मुलाकात कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुलाकात की जानकारी खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर दी। एस जयशंकर ने लिखा कि जोहान्सबर्ग में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले सीपीसी पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलने का अवसर मिला।

गौरतलब है कि इसके पहले दोनों नेता ब्राजील में

18 नवंबर 2024 को मिले थे और आपसी संबंधों पर आगे बढ़ने को लेकर चर्चा की थी। इसके बाद ही दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ के पिघलने के आसार बढ़ने लगे थे। इसका असर इसी साल जनवरी में पहली बार दिखा, जब भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 26 और 27 जनवरी को चीन का दौरा किया और चीन के अधिकारियों में भेंट-मुलाकात की। इसका जिक्र करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना कि दोनों मंत्रियों ने इस बैठक के दौरान खास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के साथ ही, कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीधी उड़ान के जरिए कनेक्टिविटी की बहाली और दोनों देशों के आपसी यात्रियों की सहूलियतों को बढ़ाने पर चर्चा हुई।

वैसे देखें तो दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने और नई सदी के अनुरूप ढालने की दिशा में जमीनी स्तर पर काम करने की भूमिका पिछले साल अक्टूबर में रूसी शहर कजान में हुई चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपसी बैठक के साथ बननी शुरू हुई। इसके बाद से ही चीन और भारत अपनी वैश्विक उपस्थिति और महत्ता को समझने लगे हैं। शायद यही वजह है कि जोहान्सबर्ग में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आपसी बैठक में उस जी-20 को लेकर भी चर्चा की,, जिसकी बैठक में शामिल होने दोनों गए हैं। इसके साथ ही आपस के लिए बेहद अहम शंघाई सहयोग संगठन को लेकर भी वैचारिक आदान-प्रदान हुआ।

दोनों विदेश मंत्रियों की आपसी चर्चा के बाद 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरूआत होने जा रही है। लेकिन यात्रा का तंत्र क्या होगा और उसके तरीके क्या होंगे, इसे लेकर अभी फाइनल स्तर पर बात नहीं बनी है। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों देशों के अधिकारी इस बारे में मिलकर चर्चा करेंगे और तंत्र बनाने को लेकर जल्द ही आखिरी स्तर पर पहुंचा जा सकेगा। यहां यह भी ध्यान रखना है कि भारत की ओर से हर साल जून और सितंबर के बीच उत्तराखंड में लिपुलेख और सिक्किम के नाथू ला दर्रे के जरिए केएमवाई का आयोजन किया जाता है। यह भी ध्यान देना चाहिए कि 2020 में आई कोरोना महामारी और कुछ दूसरी वजहों से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें रोक दी गईं। माना जा रहा है कि जयशंकर और वांग यी की मुलाकात के बाद ये उड़ाने फिर से शुरू हो सकेंगी। बंद होने से पहले दोनों देशों के बीच हर महीने 539 सीधी उड़ानों के जरिए करीब 1.25 लाख से ज्यादा यात्रियों की दोनों तरफ आवाजाही थी। माना जा रहा है कि ये सेवा जल्द शुरू होगी और अब इससे ज्यादा यात्रियों की हर महीने दोनों देशों के बीच आवाजाही होगी।

बांग्लादेश से बिगड़े रिश्तों को पटरी पर लाने की चुनौती?

शोभना जैन

बांग्लादेश में गत अगस्त में शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच हाल ही में मस्कट में विदेश मंत्री डॉ। एस। जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन के बीच क्षेत्रीय देशों के मंच 'बिम्सटेक' और द्विपक्षीय चुनौतियों व समस्याओं पर चर्चा काफी अहम मानी जा रही है। यह बातचीत ऐसे माहौल में हुई जब बांग्लादेश में भारत विरोधी घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीते दिसंबर में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश का दौरा किया था।

इसी कड़ी में पिछले दिनों ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय विदेश मंत्री एस। जयशंकर की बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ मुलाकात हुई। यह बातचीत द्विपक्षीय संबंधों के भावी स्वरूप के अलावा बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए गठित बिम्सटेक पर मुख्य तौर पर केंद्रित थी।

बांग्लादेश बिम्सटेक की बजाय दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन 'दक्षेस' को पुन: सक्रिय कर इसे और प्रभावी बनाना चाहता है, जबकि भारत का पक्ष है कि बिम्सटेक देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने का अधिक प्रभावशाली मंच बन सकता है। सार्क देशों के क्षेत्रीय ग्रुप में जहां पाकिस्तान शामिल है, वहीं क्षेत्र के सात देशों वाले बिम्सटेक में पाकिस्तान शामिल नहीं हैं।

बिम्सटेक ग्रुप में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार और नेपाल शामिल हैं। भारत के खिलाफ पाक

स्थित और समर्थित आतंकी संगठनों द्वारा आतंकी घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान में 2016 में होने वाले 19 वें सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया था। उसके बाद कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भी सम्मेलन में नहीं जाने के बाद शिखर बैठक रद्द कर दी गई।

बिम्सटेक पर बांग्लादेश का पक्ष इसलिए भी अहम है क्योंकि बिम्सटेक की आगामी अप्रैल में प्रस्तावित शिखर बैठक में इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश को मिलने वाली है। ऐसे में अहम सवाल है कि अपनी मेजबानी में बांग्लादेश सार्क को पुनः सक्रिय करने की बाबत औपचारिक रूप से क्या पक्ष रखता है और बिम्सटेक कितना मजबूत बनता है।

हालांकि मस्कट बैठक में जयशंकर ने बांग्लादेश के बिम्सटेक के रुख पर भारत की तरफ से दोटूक असहमति जाहिर कर दी थी। ऐसी संभावना है कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मो। यूनुस और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच अप्रैल में प्रस्तावित बिम्सटेक शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात हो सकती है। ऐसे में निगाहें इस पर रहेंगी कि क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार उसे आपसी संबंधों को पटरी पर लाने का अवसर बनाती है या उसका भारत विरोधी रूख कायम रहता है।

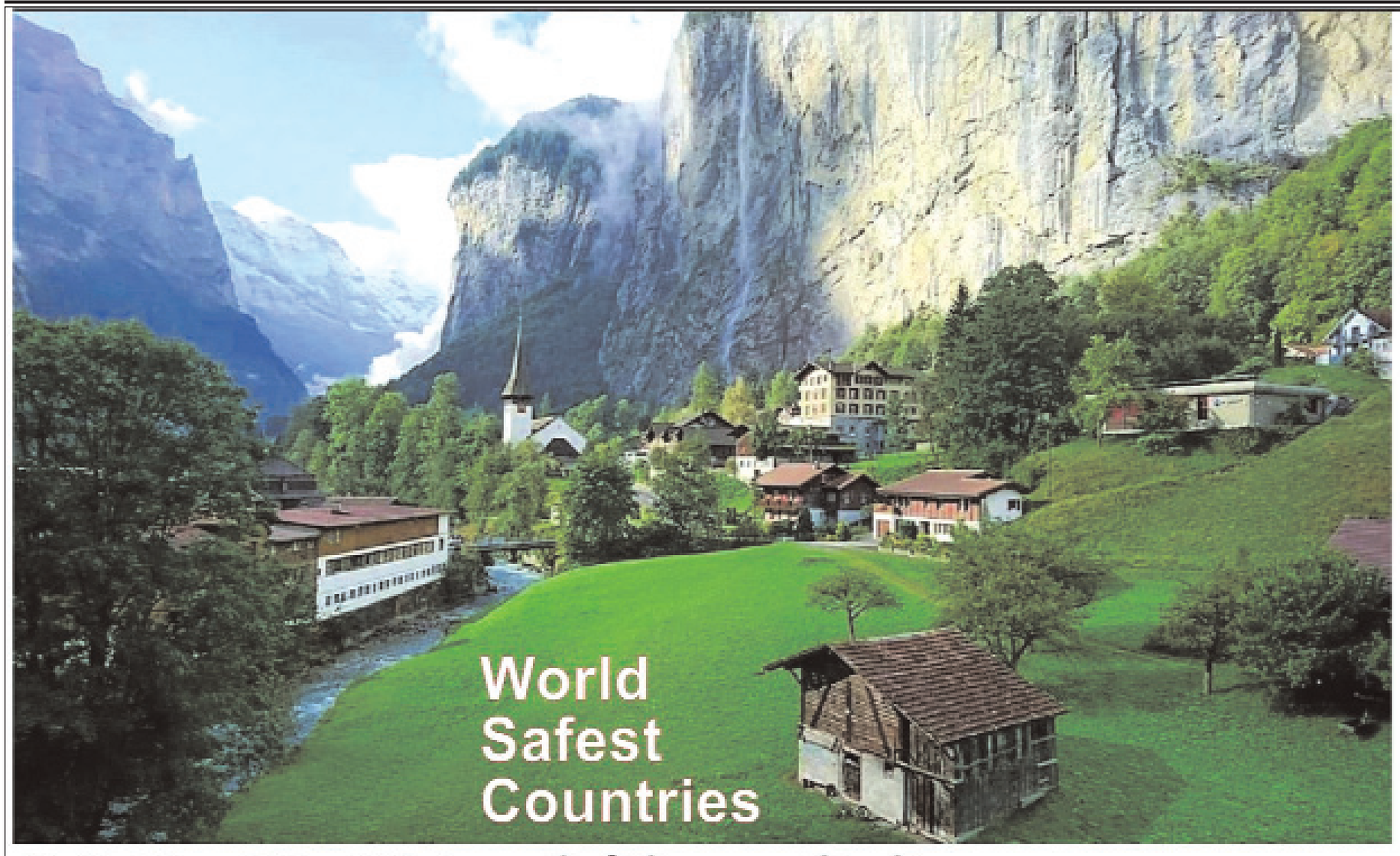

इन देशों में सुरक्षा की नहीं होगी चिंता, बेफिक्र होकर बनाएं घूमने का प्लान

कई लोग विदेश घूमने की इच्छा रखते हैं। विदेश घूमने के लिहाज से अधिकतर देश शानदार हैं। हालांकि विदेशों की खूबसूरती किसी भी टूरिस्ट के मन को आसानी से भा सकती है। लेकिन जब भी विदेश घूमने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि क्या यह जगह सुरक्षा के लिहाज से सही है। क्योंकि सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आपको सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं कि वह कौन-कौन से देश हैं, जहां पर आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं।

आइसलैंड

आइसलैंड की आबादी 3,72,295 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार, यह दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। बता दें कि यहां पर क्राइम रेट काफी कम है। इसके साथ ही यह हाई-सिक्योरिटी वाला देश भी है। सभी तरह के अपराधों के प्रति यहां के नागरिकों का एक मजबूत सामाजिक दृष्टिकोण है। यह देश धार्मिक स्वतंत्रता देने के साथ ही महिलाओम और पुरुषों को समान अधिकार देता है। अगर आप भी विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आइसलैंड सुरक्षित देश है।

न्यूजीलैंड

आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की जनसंख्या 5,124,100 के आसपास है। यह देश भी घूमने और रहने के लिहाज से सुरक्षित है। यहां पर आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। न्यूजीलैंड का भी क्राइम रेट कम है। हालांकि साल 2019 में क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों पर हुए आतंकवादी हमले के कारण यहां का क्राइम स्कोर थोड़ा कम हो गया है। यह पर आप सुरक्षा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड में शांति वाले इलाके में पुलिस अपने पास हथियार भी नहीं रखती है।

पुर्तगाल

साल 2014 के अनुसार, पुर्तगाल दुनिया का 18वां सबसे सुरक्षित देश है। ऐसे में आप बिना सुरक्षा की चिंता किए बगैर यहां पर घूम सकते हैं। 10,270,865 के करीब आबादी वाला यह देश विभिन्न कारणों से सबसे सुरक्षित देशों में शीर्ष 5वां स्थान अर्जित किया है। बता दें कि आर्थिक विकास के कारण इस देश की बेरोजगारी दर 17 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक कम हो गई है।

आस्ट्रिया

26,177,413 के करीब जनसंख्या वाला देश आस्ट्रिया भी सुरक्षित देशों की गिनती में आता है। यहां पर भी अपराध दर काफी कम है। लेकिन यहां पर घूमने आने वाले टूरिस्टों और यहां पर रहने वाले स्थानीय निवासियों को जेबकतरों और पर्स-स्नैचर्स आदि घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी यहां पर घूमने आना चाहते हैं तो

आपको जेबकतरों से सावधान रहने की जरूरत होगी।

डेनमार्क

डेनमार्क 5,896,026 आबादी वाला देश है। बता दें कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार, यह दुनिया का 5वां सबसे सुरक्षित देश है। इस देश में अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और कम भ्रष्टाचार होने के साथ ही कुशल सुरक्षाबल मिलेगा। इसके अलावा यहां की हेल्थ सुविधाएं भी काफी बेहतर हैं। इस देश में लोग आरामदायक तरीके से अपनी जीवन व्यतीत करते हैं।

कनाडा

कनाडा की कुल आबादी 37,742,154 के करीब है। आबादी के लिहाज से कनाडा काफी छोटा देश है। यहां का अधिकार हिस्सा बंजर जंगल है और यह बंजर जंगल हजारों मीलों तक फैला हुआ है। लेकिन घूमने के लिहाज से यह काफी सुरक्षित देश है। इस देश का अपराध दर भी काफी कम है।

सिंगापुर

सिंगापुर 59,43,546 के करीब आबादी वाला है। सिंगापुर में छोटी-मोटी चोरी और अन्य अपराधों के खिलाफ कुछ सख्त कानून हैं। जिसके कारण इसकी गिनती दुनिया के सुरक्षित देशों में होती है। हालांकि सिंगापुर को शहर-राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यह दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे सुरक्षित राज्य है।

जापान

जापान की जनसंख्या 125.93 मिलियन के आसपास है। सुरक्षा के लिहाज से यह सबसे सुरक्षित देश है। चीन और उत्तर कोरिया के करीब होने के बाद भी जापान एशियाई महाद्वीप का एक सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्थिर देश है। वैश्विक शांति सूचकांक में जापान हमेशा हाई स्कोर हासिल करता है।

चेक गणराज्य

चेक गणराज्य की आबादी 10,512,397 के करीब है। यहां पर हर वर्ष अपराध दर घटता प्रतीत होता है। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में चेक गणराज्य सुरक्षित देशों में से एक है। यहां पर आप सुरक्षा की परवाह किए बिना आराम से घूम-फिर सकते हैं।

स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड घूमने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट यहां पहुंचते हैं। बता दें कि यहां की आबादी 8.6 मिलियन के आसपास है। रहने और घूमने के लिहाज से यह देश सबसे ज्यादा बेस्ट है। फूड सिक्योरिटी के मामले में भी स्विट्जरलैंड दुनिया भर में चौथे स्थान पर है।

सिक्किम घूमने का बना रहे हैं प्लान तो...

इन खूबसूरत जगहों को करें एक्सप्लोर, जन्नत में आने का होगा एहसास

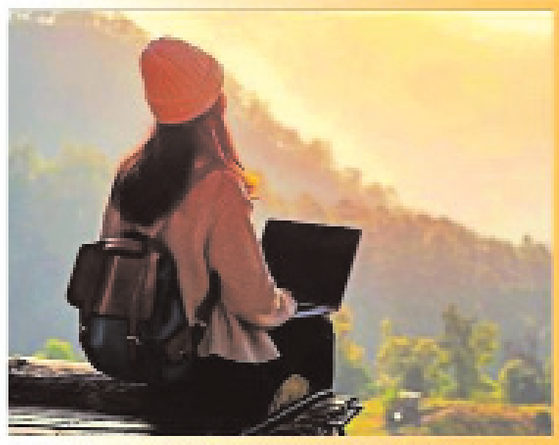

देश की टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन्स में नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों का नाम गिना जाता है। नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप प्लान करने वाले अधिकतर लोग सिक्किम घूमना नहीं भूलते हैं। वैसे तो सिक्किम्म में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहे हैं। ऐसे में अगर आप भी सिक्किम घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को एक्सप्लोर करना न भूलें। इन खूबसूरत जगहों पर घूमने के बाद आपका वापस आने का दिल नहीं करेगा। हिमालय की गोद में बसा सिक्किम भले ही एक छोटा सा राज्य है। लेकिन यहां की खूबसूरत वादियों से लेकर नेचर की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको सिक्किम की कुछ शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में...

त्सोमगो झील की सैर

अगर आप सिक्किम में किसी रोमांटिक जगह पर घूमना चाहते हैं तो त्सोमगो लेक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। त्सोमगो लेक सिक्किम की राजधानी गंगटोक से महज 40 किलोमीटर दूर है। यह लेक 12,400 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस लेक को चांगु झील के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि सर्दियों में यह लेक पूरी तरह से जम जाती है। वहीं बसंत ऋतु के मौके पर इस लेक की सुंदरता कई खूबसूरत फूलों से खिल उठती है।

जुलुक का दीदार

जुलुक का दीदार करने के लिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 3 घंटे का सफर तय करना होता है। इस दौरान रास्ते में 32 हेयरपिन मोड़ आपकी यात्रा को अधिक शानदार बना सकते हैं। वैसे तो जुलुक सिक्किम का एक छोटा सा और काफी खूबसूरत गांव है। लेकिन यहां से 11 फीट की ऊंचाई पर स्थित थंबी व्यू प्वाइंट कंचनजंघा चोटी अपने खूबसूरत नजारों के लिए फेमस है। जुलुक की ट्रिप के दौरान कुपुप लेक या हाथी झील का भी दीदार कर सकते हैं।

पेलिंग की ट्रिप

गंगटोक से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पेलिंग भी घूमने के लिए बेस्ट जगह है। यह जगह रोमांच के लिए फेमस है। पेलिंग का सफर एडवेंचर लवर्स के लिए बेस्ट हो सकता है। यहां पर एडवेंचर के शौकीन लोग रॉक क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, कयाकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग जैसी कई एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा सांगाचोएलिंग मठ रिम्बी वॉटरफॉल स्काई वॉक और सेवारो रॉक गार्डन का दीदार कर अपने सफर को शानदार और रोमांचक बना सकते हैं।

रवंगला

रवंगला सिक्किम का खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय पर्वतों से घिरा रवंगला मैनम और तेंडोंग हिल्स टॉप पर मौजूद है। बता दें कि रवंगला गंगटोक से लगभग 63 किलोमीटर की दूर स्थित है। नेचर लवर्स के लिए रवंगला की सैर बेस्ट हो सकती है। यहां से आप ग्रेटर हिमालय के मनमोहक नजारों को बेहद नजदीक से देख सकते हैं।

इन टिप्स को फॉलो कर हॉलिडे को बनाएं शानदार, ऐसे करें पैसों की बचत

कई लोगों को घूमना काफी पसंद होता है। कई बार लगातार ट्रैवल करने के बाद भी थकान नहीं होती है। लेकिन घूमने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। ऐसे में सेविंग्स का होना जरूरी होता है। घूमने के दौरान कई बार ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से घूमने की प्लानिंग करें तो आप पैसों की बचत कर सकते हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ट्रैवल के कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं। जिनकी मदद से आप ट्रैवल भी कर लेंगे और पैसों की सेविंग भी कर लेंगे।

हॉलिडे की योजना

अगर आप भी छुट्टी पर जाने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यह डिसाइड करें की आप रिलैक्सिंग हॉलिडे के लिए समुद्र तट पर चाहते हैं या एडवेंचर्स करना चाहते हैं। जब आपको यह पता होता है कि आप घूमने के लिए कहां जाने वाले हैं तो वहां होने वाले खर्च और यात्रा कार्यक्रम की योजना पहले से बना लें। इस दौरान आपके लिए रियलिस्टिक बजट बनाना आसान हो जाएगा।

रियलिस्टिक बजट

घूमने जाने की शुरूआत हॉलिडे रीयलिस्टिक बजट तय करने से शुरू होती है। आप कहीं भी घूमने जा रहे हों। कोई भी स्मार्ट ट्रैवलर यह बात काफी अच्छे से जानता है कि शानदार छुट्टियां बिताने के लिए एक रियलिस्टिक बजट की जरूरत होती है। जिसे आप आसानी से पहले ही बना सकते हैं।

ट्रैवल और खरीदारी

घूमने जाने के दौरान बुकिंग या खरीदारी पर कैशबैक कमा सकते हैं। इससे आपकी ट्रैवलिंग आसान हो जाती है। कई बार खरीददारी करने पर या बुकिंग करने के दौरान आपको कैशबैक मिलता है। इसलिए हमेशा इस ऑप्शन को ओपेन रखना चाहिए।

ऑफ सीजन में यात्रा

इस सीक्रेट को सभी स्मार्ट ट्रैवलर्स अपनाते हैं। अधिकतर ट्रैवल करने वाले ऑफ सीजन में यात्रा कर बड़ी बचत करते हैं। इस दौरान उनका ज्यादा खर्च नहीं होता है। क्योंकि वह ऑफ-पीक हॉलिडे सीजन में ट्रैवल करते हैं। ऑफ सीजन में ट्रैवल करने से फ्लाइट्स, होटल आदि सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं।

फ्लाइट्स चुनते समय फ्लेक्सिबल

पर्यटकों की आवाजाही सप्ताह के कुछ दिनों में कम होती है। इस समय यात्रा करने पर आपको सस्ती उड़ान भरने का मौका मिल सकता है। फ्लाइट की कीमत के आधार पर आप अपनी छुट्टियों को प्लान कर सकते हैं। इससे भी आप अच्छी खासी सेविंग कर लेंगे।

हॉस्पिटैलिटी कंपनी

आपको बता दें कि अपने नियमित ग्राहकों के लिए कई प्रमुख होटल चेंस और एयरलाइंस बहुत कम या बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के लॉयल्टी प्रोग्राम्स पेश करती है। इस दौरान आपको होटल चेंस और एयरलाइंस के जरिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड

क्रेडिट या डेबिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। यह पॉइंट अर्जित करने का एक क्विक और आसान तरीका है। जिसके बदले कई प्रमुख बैंक गिफ्ट्स और सर्विस के बदले में आपको रिवार्ड पॉइंट प्रदान करते हैं। जिन्हें किसी भी समय रिडीम किया जा सकता है।

सस्ता विकल्प खोजें

अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप उन विकल्पों को पता करें। जिनमें यात्रा सस्ती होने के साथ ही आने-जाने से लेकर रहने तक हर चीज के लिए काफी सारे विकल्प होते हैं। इस दौरान हॉलिडे प्लान करने के दौरान शानदार अनुभवों के लिए फ्लाइट्स के स्थान पर ट्रेनों की खोज करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कैबिनेट से वक्फ बिल को मिली मंजूरी

नईदिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को वक्फ बिल को मंजूरी दे दी है। जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर इसे हरी झंडी दी गई है। इस बिल को सदन में बजट सत्र के दूसरे हिस्से में 10 मार्च के बाद पेश किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार 19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में इसके संशोधन की मंजूरी दी गई। पिछली बार इस बिल को अगस्त में सदन के अंदर पेश किया गया था। बाद में विपक्ष के हंगामे के बाद इसे जेपीसी में भेजा गया था। जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की ने नए संशोधन पर रिपोर्ट को 29 जनवरी को मंजूरी दी थी। विपक्ष ने इसको लेकर आपत्ति भी जताई थी साथ ही वक्फ बाय यूजर्स प्रावधान को हटाने के प्रस्ताव का भी विरोध किया था। वक्फ बिल को अगस्त महीने में लोकसभा के अंदर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरन रिजिजू के द्वारा पेश किए जाने के बाद जेपीसी के पास भेज दिया गया था। बाद में संसदीय समिति ने बहुमत में इसको मंजूरी दी।

डीन बनाने का मामला, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा

नई दिल्ली। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करने के आरोपी एनआईटी-कालीकट के प्रोफेसर को डीन नियुक्त करने का मामला तुल पकड़ने लगा है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस मामले में मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा यह फैसला ''गांधी का दिखावा और गोडसे का महिमामंडन करने'' की सरकार की मानसिकता का हिस्सा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कालीकट (एनआईटी) के निदेशक की ओर से जारी आदेश में डॉ. शैजा ए को 7 मार्च से योजना व विकास विभाग का डीन नियुक्त किया गया है। महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर नाथूराम गोडसे की कथित प्रशंसा करने के आरोप में डॉ. शैजा खिलाफ पुलिस में मामला लंबित है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा, केरल में एक प्रोफेसर जो सार्वजनिक रूप से कहती हैं कि उन्हें भारत को बचाने के लिए गोडसे पर गर्व है, उन्हें को मोदी सरकार ने एनआईटी-कालीकट में डीन बना दिया है।

निलंबित आप विधायकों को पुलिस ने संसद जाने से रोका

नईदिल्ली। दिल्ली विधानसभा से निलंबित आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें संसद में घुसने से रोक दिया है। विधायकों ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें विधानसभा परिसर में घुसने से रोकने के लिए एंट्री रोड पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद आप विधायक वहीं बैठ गए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हाथों में जय भीम की तख्तियां भी पकड़ी हुई थीं। आतिशी ने इस कदम की निंदा की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी ने तानाशाही को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। आतिशी ने कहा, पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि आप विधायकों को दिल्ली विधानसभा परिसर में जाने से रोक दिया गया है। वे कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर से आदेश आए हैं कि आप के विधायकों को गेट पर ही रोक लिया जाए। पूरे संसदीय इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से या संसद परिसर से एक चुने हुए विधायक को प्रवेश करने पर रोका गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ।

शीश महल की जांच शुरू करेगी दिल्ली सरकार : प्रवेश

नईदिल्ली। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि शीश महल विवाद की जांच शुरू की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में कितना सरकारी धन का इस्तेमाल किया गया था। 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले, जिसका इस्तेमाल केजरीवाल ने सीएम रहते हुए किया था, को बीजेपी ने शीश महल करार दिया है। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में आप को सत्ता से हटाने वाली भाजपा ने उन पर बंगले में लक्जरी सुविधाओं के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। सीएजी रिपोर्ट को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो 2000 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे...%शीशमहल% की भी जांच होगी। उन्होंने कहा कि आप सरकार के तहत तीन साल पहले बने भव्य मुख्यमंत्री कार्यालय की जांच की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इसके पुनर्निर्माण पर कितना पैसा खर्च किया गया था।

हाईकमान ने तय किया योगी मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला

लखनऊ। योगी मंत्रिमंडल की बहुप्रतीक्षित विस्तार जल्द ही होने जा रहा है। महाकुंभ और विधासभा का सत्र पूरा होते ही इस दिशा में काम तेज होगा। सूत्रों के अनुसार यूपी में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पार्टी हाईकमान ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक, दो-तीन मंत्रियों की जहां छुट्टी होगी, वहीं तीन-चार नए चेहरे शामिल होंगे। लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे नेताओं को होली का तोहफा देने की तैयारी है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव होगा। जिनके विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं या मंत्रियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उन्हें हटाया जाएगा। अहम विभाग के साथ पश्चिम के भी दो चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं, विस्तार में 75 वर्ष की आयु सीमा का भी ध्यान रखा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश स्तर से इस संबंध में फीडबैक लिया जा चुका है। अगले 8-10 दिनों में विस्तार होने की पूरी संभावना है।

महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट, इसने भारत की विकास यात्रा के नए अध्याय का संदेश दिया: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ को लेकर एक ब्लॉग लिखा। प्रधानमंत्री ने इस भव्य आयोजन को युग परिवर्तन की आहट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने भारत की विकास यात्रा के नए अध्याय का संदेश दिया है और यह संदेश है विकसित भारत का। उन्होंने इस आयोजन को एकता का महाकुंभ करार देते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग इस महाकुंभ में एक हो गए। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए देशवासियों की ओर से किए परिश्रम से अभीभूत पीएम मोदी सोमनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और हर भारतीय के लिए प्रार्थना करेंगे।

पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, महाकुंभ संपन्न हुआ। एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ, एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है! महाकुंभ के पूर्ण होने पर जो विचार मन में आए, उन्हें मैंने कलमबद्ध करने का प्रयास किया है।

पीएम मोदी का पूरा ब्लॉग

पीएम मोदी ने लिखा, महाकुंभ संपन्न हुआ। एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है, जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा।

उन्होंने लिखा, 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देवभक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी-देवता जुटे, संत-महात्मा जुटे, बाल-वृद्ध जुटे, महिलाएं-युवा जुटे, और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी।

उन्होंने लिखा, तीर्थराज प्रयाग के इसी क्षेत्र में एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेरपुर भी है, जहां प्रभु श्रीराम और निषादराज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वो प्रसंग भी हमारे इतिहास में भक्ति और सद्भाव के संगम की तरह ही है। प्रयागराज का ये तीर्थ आज भी हमें एकता और समरसता की वो प्रेरणा देता है।

पीएम मोदी ने लिखा, बीते 45 दिन, प्रतिदिन, मैंने देखा, कैसे देश के कोने-कोने से लाखों-लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे हैं। संगम पर स्नान की भावनाओं का ज्वार, लगातार बढ़ता ही रहा। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था- संगम में स्नान। मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन, आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए, नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर, त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को ना औपचारिक निमंत्रण था, ना ही किस समय पहुंचना है, उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस, लोग महाकुंभ चल पड़े...और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए।

उन्होंने लिखा, मैं वो तस्वीरें भूल नहीं सकता...स्नान के बाद असीम आनंद और संतोष से भरे वो चेहरे नहीं भूल सकता। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हमारे दिव्यांग जन हों, जिससे जो बन पड़ा, वो साधन करके संगम तक पहुंचा। मेरे लिए ये देखना बहुत ही सुखद रहा कि बहुत बड़ी संख्या में भारत की आज की युवा पीढ़ी प्रयागराज पहुंची। भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना, एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे ये विश्वास दृढ़ होता है कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है और इसे आगे ले जाने का दायित्व समझती है और इसे लेकर संकल्पित भी है, समर्पित भी है। इस महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचने वालों की संख्या ने निश्चित तौर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन इस महाकुंभ में हमने ये भी देखा कि जो प्रयाग नहीं पहुंच पाए, वो भी इस आयोजन से भाव-विभोर होकर जुड़े। कुंभ से लौटते हुए जो लोग त्रिवेणी तीर्थ का जल अपने साथ लेकर गए, उस जल की कुछ बूंदों ने भी करोड़ों भक्तों को कुंभ स्नान जैसा ही पुण्य दिया। कितने ही लोगों का कुंभ से वापसी के बाद गांव-गांव में जो सत्कार हुआ, जिस तरह पूरे समाज ने उनके प्रति श्रद्धा से सिर झुकाया, वो अविस्मरणीय है।

उन्होंने लिखा, उस जल की कुछ बूंदों ने भी करोड़ों भक्तों को कुंभ स्नान जैसा ही पुण्य दिया। कितने ही लोगों का कुंभ से वापसी के बाद गांव-गांव में जो सत्कार हुआ, जिस तरह पूरे समाज ने उनके प्रति श्रद्धा से सिर झुकाया, वो अविस्मरणीय है। ये कुछ ऐसा हुआ है, जो बीते कुछ दशकों में पहले कभी नहीं हुआ। ये कुछ ऐसा हुआ है, जो

आने वाली कई-कई शताब्दियों की एक नींव रख गया है। प्रयागराज में जितनी कल्पना की गई थी, उससे कहीं अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। इसकी एक वजह ये भी थी कि प्रशासन ने भी पुराने कुंभ के अनुभवों को देखते हुए ही अंदाजा लगाया था। लेकिन अमेरिका की आबादी के करीब दोगुने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया, डुबकी लगाई। आध्यात्मिक क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग करोड़ों भारतवासियों के इस उत्साह पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं, ये युग परिवर्तन की वो आहट है, जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है।

पीएम मोदी ने लिखा, साथियों, महाकुंभ की इस परंपरा से, हजारों वर्षों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को बल मिलता रहा है। हर पूर्णकुंभ में समाज की उस समय की परिस्थितियों पर ऋषियों-मुनियों, विद्वत् जनों द्वारा 45 दिनों तक मंथन होता था। इस मंथन में देश को, समाज को नए दिशा-निर्देश मिलते थे। इसके बाद हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ में परिस्थितियों और दिशा-निर्देशों की समीक्षा होती थी। 12 पूर्णकुंभ होते-होते, यानि 144 साल के अंतराल पर जो दिशा-निर्देश, जो परंपराएं पुरानी पड़ चुकी होती थीं, उन्हें त्याग दिया जाता था, आधुनिकता को स्वीकार किया जाता था और युगानुकूल परिवर्तन करके नए सिरे से नई परंपराओं को गढ़ा जाता था। 144 वर्षों के बाद होने वाले महाकुंभ में ऋषियों-मुनियों द्वारा, उस समय-काल और परिस्थितियों को देखते हुए नए संदेश भी दिए जाते थे। अब इस बार 144 वर्षों के बाद पड़े इस तरह के पूर्ण महाकुंभ ने भी हमें भारत की विकासयात्रा के नए अध्याय का संदेश दिया है। ये संदेश है- विकसित भारत का।

उन्होंने लिखा, जिस तरह एकता के महाकुंभ में हर श्रद्धालु, चाहे वो गरीब हों या संपन्न हों, बाल हो या वृद्ध हो, देश से आया हो या विदेश से आया हो, गांव का हो या शहर का हो, पूर्व से हो या पश्चिम से हो, उत्तर से हो दक्षिण से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी विचारधारा का हो, सब एक महायज्ञ के लिए एकता के महाकुंभ में एक हो गए। एक भारत-श्रेष्ठ भारत का ये चिर स्मरणीय दृश्य, करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया। अब इसी तरह हमें एक होकर विकसित भारत के महायज्ञ के लिए जुट जाना है।

पीएम मोदी ने लिखा, साथियों, आज मुझे वो प्रसंग भी याद आ रहा है जब बालक रूप में श्रीकृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। वैसे ही इस महाकुंभ में भारतवासियों ने और विश्व ने भारत के सामर्थ्य के विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं। हमें अब इसी आत्मविश्वास से एक निष्ठ होकर, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। भारत की ये एक ऐसी शक्ति है, जिसके बारे में भक्ति आंदोलन में हमारे संतों ने राष्ट्र के हर कोने में अलख जगाई थी। विवेकानंद हों या श्री ऑरोबिंदो हों, हर किसी ने हमें इसके बारे में जागरूक किया था। इसकी अनुभूति गांधी जी ने भी आजादी के आंदोलन के समय की थी। आजादी के बाद भारत की इस शक्ति के विराट स्वरूप को यदि हमने जाना होता, और इस शक्ति को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता, तो ये गुलामी के प्रभावों से बाहर निकलते भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन हम तब ये नहीं कर पाए। अब मुझे संतोष है, खुशी है कि जनता जनार्दन की यही शक्ति, विकसित भारत के लिए एकजुट हो रही है।

उन्होंने लिखा, वेद से विवेकानंद तक और उपनिषद से उपग्रह तक, भारत की महान परंपराओं ने इस राष्ट्र को गढ़ा है। मेरी कामना है, एक नागरिक के नाते, अनन्य भक्ति भाव से, अपने पूर्वजों का, हमारे ऋषियों-मुनियों का पुण्य स्मरण करते हुए, एकता के महाकुंभ से हम नई प्रेरणा लेते हुए, नए संकल्पों को साथ लेकर चलें। हम एकता के महामंत्र को जीवन मंत्र बनाएं, देश सेवा में ही देव सेवा, जीव सेवा में ही शिव सेवा के भाव से स्वयं को समर्पित करें।

पीएम मोदी ने लिखा, साथियों, जब मैं काशी चुनाव के लिए गया था, तो मेरे अंतरमन के भाव शब्दों में प्रकट हुए थे, और मैंने कहा था- मां गंगा ने मुझे बुलाया है। इसमें एक दायित्व बोध भी था, हमारी मां स्वरूपा नदियों की पवित्रता को लेकर, स्वच्छता को लेकर। प्रयागराज में भी गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम पर मेरा ये संकल्प और दृढ़ हुआ है। गंगा जी, यमुना जी, हमारी नदियों की स्वच्छता हमारी जीवन यात्रा से जुड़ी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नदी चाहे छोटी हो या बड़ी, हर नदी को जीवनदायिनी मां का प्रतिरूप मानते हुए हम अपने यहां सुविधा के अनुसार, नदी उत्सव जरूर मनाएं। ये एकता का महाकुंभ हमें इस बात की प्रेरणा देकर गया है कि हम अपनी नदियों को निरंतर स्वच्छ रखें, इस अभियान को निरंतर मजबूत करते रहें।

उन्होंने आगे लिखा, मैं जानता हूं, इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से...मां यमुना से...मां सरस्वती से...हे मां हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा...। जनता जनार्दन, जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो, तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमाप्रार्थी हूं।

पीएम मोदी ने लिखा, साथियों, श्रद्धा से भरे जो करोड़ों लोग प्रयाग पहुंचकर इस एकता के महाकुंभ का हिस्सा बने, उनकी सेवा का दायित्व भी श्रद्धा के सामर्थ्य से ही पूरा हुआ है। यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर, इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य हो, यहां ना कोई शासक था, ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। हमारे सफाईकर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, नाविक साथी, वाहन चालक, भोजन बनाने वाले, सभी ने पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से निरंतर काम करके इस महाकुंभ को सफल बनाया। विशेषकर, प्रयागराज के निवासियों ने इन 45 दिनों में तमाम परेशानियों को उठाकर भी जिस तरह श्रद्धालुओं की सेवा की है, वह अतुलनीय है। मैं प्रयागराज के सभी निवासियों का, यूपी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं।

अंत में पीएम मोदी ने लिखा, साथियों, महाकुंभ के दृश्यों को देखकर, बहुत प्रारंभ से ही मेरे मन में जो भाव जगे, जो पिछले 45 दिनों में और अधिक पुष्ट हुए हैं, राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य को लेकर मेरी आस्था, अनेक गुना मजबूत हुई है। 140 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह प्रयागराज में एकता के महाकुंभ को आज के विश्व की एक महान पहचान बना दिया, वो अद्भुत है। देशवासियों के इस परिश्रम से, उनके प्रयास से, उनके संकल्प से अभीभूत मैं जल्द ही द्वादश ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग, श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा और श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। महाकुंभ का स्थूल स्वरूप महाशिवरात्रि को पूर्णता प्राप्त कर गया है। लेकिन मुझे विश्वास है, मां गंगा की अविरल धारा की तरह, महाकुंभ की आध्यात्मिक चेतना की धारा और एकता की धारा निरंतर बहती रहेगी।

खेल
प्रमुख समाचार

सेमीफाइनल में भारत की किस टीम से होगी भिड़ंत?

दुबई। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप-बी से सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग दिलचस्प हो चुकी है। बुधवार को अफगानिस्तान की इंग्लैंड पर जीत ने इस रेस को दिलचस्प बना दिया है। इंग्लैंड की टीम ग्रुप-बी से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। हालांकि, ग्रुप-बी से अब भी तीनों टीम दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस में बनी हुई है और तीनों को एक जीत सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है। ग्रुप-ए से सेमीफाइनल की दो टीमें पहले ही तय हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड और भारत पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में अपना स्थान बुक कर चुके हैं, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इन दोनों का अपने ग्रुप में स्थान क्या रहेगा। ग्रुप ए और बी, दोनों में अभी दो-दो मैच बचे हैं।

ग्रुप-ए से अंक तालिका का समीकरण दो मार्च को तय होगा, जब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। इस मैच से तय होगा कि भारत अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहेगा या दूसरे स्थान पर। ग्रुप-ए से शीर्ष पर रहने वाली टीम का सेमीफाइनल में ग्रुप-बी में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम से सामना होगा, जबकि ग्रुप-ए में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम ग्रुप-बी की शीर्ष स्थान पर रहने वाली टीम से भिड़ेगी। ग्रुप-ए का दूसरा मैच गुरुवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच है, लेकिन यह मैच महज औपचारिकता ही है, क्योंकि दोनों टीमें पहले ही बाहर हो चुकी हैं।

ग्रुप बी के अंतिम दो मैचों में अफगानिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका का सामना इंग्लैंड से होगा। अगर दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया अपने-अपने मैच जीत जाते हैं, तो वे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हरा देता है तो उसके साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से बिना भिड़े क्वालिफाई कर जाएगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 74,612 और निफ्टी 22,545 पर फ्लैट बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार (27 फरवरी) को बेहद सिमित दायरे में कारोबार करते हुए अंत में लगभग सपाट बंद हुए। वहीं, ब्रोडर मार्केट में भारी बिकवाली का दबाव देखा गया। मंथली डेरिवेटिव एक्सपायरी और इस सप्ताह के अंत में जीडीपी डेटा जारी होने से पहले निवेशक सावधानी बरत रहे हैं। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज 100 से ज्यादा अंक चढ़कर 74,706 पर खुला। हालांकि, कुछ ही देर में यह सपाट स्तर पर गया। पूरे सेशन में सिमित दायरे में कारोबार करने के बाद सेंसेक्स 10.31 अंक या 0.01त्न की मामूली बढ़त लेकर 74,612 के स्तर पर लगभग सपाट बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ़्टी50 भी आज मजबूती के साथ 22,613 अंक पर खुला। मगर खुलने के कुछ ही देर में यह लगभग सपाट स्तर पर आ गया। अंत में निफ्टी 2.50 अंक या 0.01त्न की मामूली गिरावट लेकर 22,545 पर क्लोज हुआ।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक ने जताया भरोसा

नई दिल्ली। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसा जताया है। बुधवार को एडवांटेज असम 2.0 व्यापार सम्मेलन में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कोउमे ने निवेशकों से भारत में निवेश का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि थोड़ी मंदी के बावजूद भारत का भविष्य उज्जवल है। विश्व बैंक भारत की आर्थिक संभावनाओं को लेकर आशावादी है। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि भारत की विकास दर में मामूली गिरावट से वह चिंतित नहीं हैं। उन्होंने भारत के प्रति अपना उत्साह जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एक फीसदी के उतार-चढ़ाव से विश्व बैंक का सकारात्मक नजरिया नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि भारत निवेश के लिए बेहतरीन जगह है। कोउमे ने कहा, हम इस समय भारत की ग्रोथ को लेकर चिंतित नहीं हैं। हम भारत को लेकर बहुत उत्साहित हैं और आगे भी उत्साहित रहेंगे।

मजबूत बैलेंस शीट ही बैंकों की स्थिरता की कुंजी : उदय कोटक

नईदिल्ली। बिज़नेस स्टैंडर्ड के वार्षिक सम्मेलन 'मंथन' में गुरुवार, 27 फरवरी को बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज और कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर और डायरेक्टर उदय कोटक ने बैंकिंग सेक्टर की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि बैंकों की बैलेंस शीट इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वे किसी भी झटके को संभाल सकें। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में फिजिकल बैंकिंग की रफ्तार धीमी होगी, जबकि डिजिटल बैंकिंग का प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि फिजिकल बैंकिंग पूरी तरह खत्म नहीं होगी, क्योंकि ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने के लिए फिजिकल ब्रांच की जरूरत बनी रहेगी। उदय कोटक का मानना है कि बैंकों की स्थिरता के लिए उनकी बैलेंस शीट का मजबूत होना आवश्यक है। बैंकिंग सेक्टर की मजबूती पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, बैंकों की बैलेंस शीट इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वे झटकों को झेल सकें।

आर्थिक मसलों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर देखना चाहिए

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को (27 फरवरी) को कहा कि राज्यों के साथ ईमानदारी से जुड़ाव होना चाहिए और आर्थिक मसलों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देखना चाहिए। उन्होंने बीएस मंथन शिखर सम्मेलन के पहले दिन बातचीत के दौरान यह बात कही। केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने भारत के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों के साथ पारदर्शी और सहयोगात्मक बातचीत की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सीतारमण ने कहा, राज्यों के साथ ईमानदार जुड़ाव होना चाहिए। आपको लगता है कि एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था से आपको इच्छा अनुसार परिणाम मिलेगा। लेकिन जीएसटी परिषद की स्थापना में भी प्रयास गहन और निरंतर थे। मुझे लगता है कि राज्यों के साथ जुड़ाव पहले होना चाहिए।

आयकर कानून के सरल होने से विवाद घटेंगे

ललित गर्ग

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 64 साल पुराने आयकर कानून-1961 के सरलीकरण और इसमें चले आ रहे बेवजह के प्रविधानों को समाप्त करने के उद्देश्य से नया इनकम टैक्स बिल-2025 पेश कर दिया। 622 पन्नों के इस विधेयक में 536 धाराएं शामिल हैं। जबकि आयकर कानून-1961 में 1647 पन्ने और 819 धाराएं रही है। इस विधेयक में कई पुराने और जटिल प्रावधानों को हटाकर करदाताओं के लिए इसे आसान और पारदर्शी बनाया गया है। नए कानून का उद्देश्य कर प्रक्रिया को स्पष्ट, सहज, सरल और कानूनी उलझनों से मुक्त बनाना है जिससे लंबे समय तक चलने वाले विवादों की संख्या कम हो। इसे लागू करने की संभावित तारीख 1 अप्रैल 2026 तय की गई है। निश्चित ही नये आयकर कानून से टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता और सरलता के नए दौर की शुरुआत होगी, यह आयकर कानून का नया सूरज है, जो जटिलताओं एवं पेचिदगियों की जगह सरलता एवं सहजता की रोशनी बनेगा।

मौजूदा आयकर कानून की तुलना में नया आयकर कानून शब्दों और धाराओं की संख्या के हिसाब से काफी छोटा है, पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 5.12 लाख शब्द थे, जबकि नए बिल में सिर्फ 2.6 लाख शब्द हैं। एक्ट के अलग-अलग चैप्टर भी 47 से घटाकर 23 कर दिए गए हैं, नए कानून में 1,200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटा दिए गए हैं। इन बदलावों का मकसद यह है कि लोग आसानी से आयकर के नियम समझ सकें और टैक्स भरने की प्रक्रिया पहले से आसान हो जाए। यह बिल आयकर प्रावधानों को सरल और आसान बनाने के बड़े मकसद से जुड़ा है, जिसका फायदा आने वाले वर्षों

में दिख सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रारंभ से ही कम-से-कम कानूनों एवं सरल-व्यवस्था के हिमायती रहे हैं।

दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर देश में आर्थिक क्रांति का शंखनाद अनेक मोर्चे पर हो रहा है। न केवल भारत की अर्थव्यवस्था बदली है बल्कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया बदल चुकी है। 1961 में बने आयकर कानून में बदलती जरूरत के मुताबिक नए-नए संशोधन होते रहे, जिससे इसकी जटिलता बढ़ती चली गई। यह जटिलता न केवल करदाताओं को उलझन में डालती थी बल्कि कानूनी प्रावधानों की कई तरह से व्याख्या अनेक उलझने एवं विवाद खड़ा करती रही है। इन जटिल होती परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि अपने देश में टैक्स को लेकर विवाद लगातार बढते गये। इन लगातार बढ़ते विवादों के कारण ही इसे दुनिया की टैक्स विवादों की राजधानी कहा जाने लगा। खासकर पिछले करीब डेढ दशक में यह ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा। नौबत ऐसी आ गई कि 2023-24 तक टैक्स संबंधी मुकदमों में विवादित रकम बढ़कर 15.4 लाख करोड़ रुपये हो गई, जिसका करीब 87 प्रतिशत हिस्सा डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा है। संभावनाएं हैं एवं सराहनीय भी है कि नये कानून के लागू होने से विवाद भी कम होंगे एवं जनता भी राहत की सांस लेगी। निश्चित ही यह कदम स्वागतयोग्य है। इस कानून को लाकर मोदी सरकार और विशेषत: वित्तमंत्री ने अपने दायित्व का ईमानदारी से पालन किया है। आयकर कानून-1961 की जटिलताओं के कारण विवादों का अंबार लगा रहा है। जबकि आयकर विभाग को इन विवादों से कोई फायदा भी नहीं होता है क्योंकि इनमें जीत का उसका रेकॉर्ड बड़ा खराब रहा है। ऑर्गनाइजेशन फॉर इकॉनमिक कोऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट (ओईसीडी) की ओर से 34 देशों में टैक्स विवादों पर हुई एक स्टडी के मुताबिक 2015 में भारत में टैक्स विभाग को महज 11.5 प्रतिशत मामलों में ही जीत मिली थी। ओईसीडी देशों का औसत इस मामले में 65 प्रतिशत है। अवश्य ही यह स्थिति भारत के लिये चिन्ताजनक रही है। अब इस स्थिति में सुधार होने की संभावना है। आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो नए आयकर कानून से कर संहिता अधिक सरल हो जाएगी और वह आयकर अधिकारियों के साथ आयकरदाताओं को भी राहत प्रदान करेगी। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि आयकरदाताओं को जटिल नियमों के साथ आसानी से समझ न आने वाली भाषा से छुटकारा मिले।

बलात्कार की घटना में टॉप पर राजधानी, विस में पेश हुए चौंकाने वाले आंकड़े

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से रेप, लूट, मर्डर और चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। तेजी से बढ़ते अपराध का मुद्दा अब विधानसभा तक पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्व मंत्री और खरसीया विधायक उमेश पटेल ने सदन के पटल पर सवाल रखते हुए पूछा कि प्रदेश में जनवरी 2024 से 2025 तक हत्या, लूटपाट, अपहरण, चोरी, डकैती और बलात्कार के कितने मामले दर्ज हुए? इसके साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि रायगढ़ जिले में अपराध की स्थिति क्या है? अपराध रोकने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

उमेश पटेल के सवालों पर जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि रायगढ़ जिला हत्या के मामले में तीसरा, लूट में पांचवा, अपहण में दसवां, चोरी में पांचवा, डकैती में पांचवा और बलात्कार के मामले में छठवें स्थान पर है।

वहीं, बात करें पूरे प्रदेश की तो छत्तीसगढ़ में साल 2024 से 2025 के बीच हत्या के 1114, लूट के 458, अपहरण के 3644, चोरी के 7960, डकैती के 56 और बलात्कार के 3191 मामले दर्ज किए गए हैं।

बता करें राजधानी रायपुर की तो डकैती को छोड़कर हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार के मामलों में राजधानी रायपुर टॉप पर है। यहां पिछले एक साल में हत्या के 93, लूट के 80, अपहरण के 515, चोरी के 1645, डकैती के 9 और बलात्कार के 268 केस दर्ज किए गए। वहीं, छत्तीसगढ़ में रेप के आंकड़े चौकाने वाले हैं।

प्रदेश में एक साल के भीतर बलात्कार के 3191 केस दर्ज किए गए हैं। रोजाना के हिसाब से इस आंकड़े को देखा जाएगा (3191/365) तो प्रदेश में औसतन 8 से 9 लोगों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में हर 3 से 4 घंटे में एक युवती या महिला के साथ रेप हो रहा है।

भावना बोहरा ने विधानसभा में उठाए विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दे

पंडरिया विधानसभा विधायक भावना बोहरा ने गुरुवार को विधानसभा में क्षेत्रीय विकास से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया। उन्होंने फूड पार्क की स्थापना, उप अभियंताओं की नियुक्ति, सड़क निर्माण कार्यों और मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के संबंध में सरकार से जवाब मांगा।

फूड पार्क की स्थापना पर सवाल-विधायक बोहरा ने पूछा कि क्या ग्राम कुई में फूड पार्क की स्थापना हेतु शासकीय भूमि को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया है? इस पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि भूमि का आधिपत्य राजस्व विभाग से उद्योग विभाग को सौंपा गया है और आवश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संशोधन पश्चात औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति लेकर कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

भावना बोहरा ने जोर दिया कि इस फूड पार्क से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसलिए इसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। उन्होंने नई औद्योगिक नीति के तहत उद्योग स्थापित करने वालों को दी जाने वाली सब्सिडी और छूट पर भी सवाल उठाया, जिसका जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि उद्योग नीति के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

उप अभियंताओं की नियुक्ति पर सवाल-नगर पालिका पंडरिया, नगर पंचायत पांडातराई एवं इंदौरी में उप अभियंताओं की नियुक्ति के संबंध में विधायक बोहरा ने पूछा कि रिक्त पदों को भरने की क्या योजना है? उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने लिखित जवाब में बताया कि उप अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है और वर्तमान में समीपस्थ निकायों के अभियंताओं को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

सड़क निर्माण कार्यों पर उठे सवाल- विधायक बोहरा ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में बजट वर्ष 2024-25 के अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों की स्थिति पर जानकारी मांगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कुल 8 सड़क निर्माण कार्य और 1 भवन निर्माण कार्य के लिए 2964.26 लाख रुपये के टेंडर जारी किए गए हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मनरेगा की है महत्वपूर्ण भूमिकाः मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में मनरेगा कार्यों को सर्वोच्च गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि अधिकतम ग्रामीण परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष रूप से गांवों में धरसा पहुंच मार्ग निर्माण और अमृत सरोवर परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती मिले और जल संरक्षण को बढ़ावा मिले। मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों को आत्मनिर्भर बनाना है। मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लागू किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ताकि यह योजना गरीबों के सशक्तिकरण में एक मजबूत आधार बने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मनरेगा को अन्य योजनाओं से जोड़कर ग्रामीण विकास की गति तेज करने पर जोर दिया जा रहा है।

राज्य में मनरेगा के प्रभावशाली क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा- बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 की प्रगति, लेबर बजट 2025-26, योजना के प्रमुख इंडिकेटर्स और अभिसरण (कॉन्वर्जेंस) मॉडल पर गहन समीक्षा की गई। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। मनरेगा आयुक्त रजत बंसल ने जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 38.52 लाख पंजीकृत परिवारों में से 24.89 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है।अमृत सरोवर योजना के तहत 2,902 जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 1,095 स्वीकृत हो चुके हैं, 299 पूर्ण हो चुके हैं, और 472 पर कार्य प्रगति पर है।

फिल्मफेयर अवार्ड कलाकारों को सम्मान

रायपुर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में चिन्हारी फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी कलाकारों का मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द हम छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा करने के लिए संकल्पित हैं और कलाकारों को शासन योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिले इसका प्रयास कर रहे है। आज 4 अलंकृत विभूतियों का कार्यक्रम में शामिल होना दर्शाता है कि कार्यक्रम कितना अच्छा और सफल है।

कांग्रेस शासनकाल में लगातार चला धर्मांतरण का खेलः ठाकुर

सुकमा एसपी और बस्तर कमिश्नर की चेतावनी के बावजूद कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आंख मूंदे रही

मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल की दिल्ली में मिशनरियों से छिपी मुलाक़ातें होती थी - देवलाल ठाकुर

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में लगातार चला धर्मांतरण का खेल चला। मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल की दिल्ली में मिशनरियों से छिपी मुलाक़ातें होती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक चंदन कश्यप के द्वारा बक़ायदा सार्वजनिक रूप से मिशनरियों को उकसाया गया और कहा गया कि वे उनके साथ हैं। कांग्रेस शासनकाल में लगातार प्रदेश में धर्मांतरण हुआ। कांग्रेस शासनकाल में धर्मांतरण की आग में पूरा बस्तर जल रहा था। नारायणपुर में धर्मांतरित लोग मूल आदिवासियों पर हमला करते रहे,

पुलिस को दौड़ा-दौड़ा कर मारा जाता था, पर प्रदेश की तत्कालिक भूपेश सरकार मुंह में दही जमाए बैठी रही। यही दृश्य फिर जगदलपुर के भेजरीपदर में दोहराया जाता है। सुकमा एसपी और बस्तर कमिश्नर की चेतावनी के बावजूद कांग्रेस की भूपेश सरकार न केवल आंख मूंदे रही बल्कि दिल्ली में बकायदा मिशनरियों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढाया।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि राजधानी में मिशनरी ने तिरंगा और संविधान जला देने की बात की थी लेकिन विरोध करने पर भूपेश जी की तब की सरकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं और विहिप के लोगों को ही बंद कर दिया था भूपेश के इस प्रश्रय के कारण धर्मांतरण बढ़ा। हमेशा से कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति के तहत ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा देती है। इस मामले में सोनिया गांधीजी हमेशा से संदिग्ध रहीं हैं। उन्होंने कहा कि यूएस फंड भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए था। अमरीका के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन 'किसी और' की सरकार भारत में बनवाना चाह रहे थे। यह 'किसी और' कौन था, इसे भूपेश बेहतर जानते हैं। बौखलाहट ही इसी बात की है कि एक बड़ी रकम से हाथ धोना पड़ा। चुनाव भी हार गये। सीनियर बघेल के हिंदू विरोधी विरासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं भूपेशजी। इसलिए कुंभ तक से इन्हें आपत्ति है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

राज्यपाल के अभिभाषण पर आपत्ति जताई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों के इतिहास में पहली बार गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के सोमवार को दिए अभिभाषण पर विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति दर्ज किया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह ने व्यवस्था दी की अभिभाषण पर चर्चा कर इसका निराकरण किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होने से पहले भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने अभिभाषण के एक बिंदु पर प्रश्न उठाया और कहा कि महामहिम से ऐसा कथन नहीं कहलवाना थी। चंद्राकर ने कहा कि अभिभाषण के पृष्ठ 14 में उल्लेख किया गया है कि मेरी सरकार 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई करवा रही है। चंद्राकर ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी भाषाएं है जिसमें पढ़ाई हो रही है। यह उल्लेख टंकण त्रुटि है या सत्य है यह सत्यापित किया जाना चाहिए। मेरा कहना है कि महामहिम से ऐसा कथन नहीं कहलवाना था। इस पर विधानसभा डॉ रमन सिंह ने व्यवस्था दी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सदन में मौजूद हैं, वे इसका निराकरण अभिभाषण पर चर्चा कर उत्तर देंगे तब इस पर प्रकाश डालेंगे।

ईडी के द्वारा विद्वेषपूर्वक कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री को घंटों रोकना गलत

रायपुर। ईडी के द्वारा भेजे गये सम्मन के आधार पर जानकारी देने गये कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू को जबरिया ईडी ऑफिस में घंटों बैठाया जाना बेहद ही आपत्तिजनक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ईडी ने कांग्रेस से उसके जिला कार्यालय के संबंध में जानकारी मांगी थी। प्रभारी महामंत्री ईडी के द्वारा चाही गयी जानकारी को देने ईडी ऑफिस गये थे। जानकारी प्राप्त करने के तुरंत बाद ईडी को उनको वापस आने देना चाहिये था। ईडी को कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिये थी तो उसको वह लिखित में मांग सकती थी, उस जानकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। कांग्रेस अपने निर्माण के एक-एक रू. का हिसाब देगी। ईडी ने भाजपा के इशारे पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी को अनावश्यक घंटों बैठाये रखा है। ईडी भाजपा के अनुषांगिक संगठन की भांति काम कर रही है जो सर्वथा अस्वीकार्य है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ईडी को राजनैतिक दल के कार्यक्रमों के खर्चों एवं पार्टी दफ्तर के निर्माण का ब्यौरा जानने का इतना ही शौक है तो सिर्फ कांग्रेस का ही क्यों वह भाजपा के भी खर्चों की पड़ताल करे। ईडी में साहस है तो वह भाजपा के 150 करोड़ रू. की लागत से बने भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे को बनाने का रुपया कहां से आया इसकी जांच करे?

एक मार्च को पंजाब पीसीसी की बैठक लेंगे भूपेश

रायपुर. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां चतुर्थ तल पर स्थित महासचिव कार्यालय में राष्ट्रीय मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने बघेल से मुलाकात की. बता दें कि नवनिर्मित कांग्रेस का मुख्यालय 9 कोटला मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है. महासचिव भूपेश बघेल कल नई दिल्ली से पंजाब के अमृतसर के लिए रवाना होंगे. एक मार्च को पंजाब के प्रभारी बघेल चंडीगढ़ स्थित पंजाब पीसीसी कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक लेंगे. साथ ही पंजाब के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगे. इसके अलावा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, राम तीर्थ मंदिर और दुर्गियाना मंदिर के दर्शन भी करेंगे.

8-अंडर 61 का शानदार स्कोर बनाकर शीर्ष पर पहुंचे शौर्य

नया रायपुर। दिल्ली के शौर्य भट्टाचार्य ने सेल छत्तीसगढ़ ओपन 2025 के तीसरे दिन 8-अंडर 61 का शानदार स्कोर बनाया, जिससे वे नया रायपुर के फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिसॉर्ट में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में शीर्ष पर पहुंच गए। शौर्य ने अब दूसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी से पांच शॉट की बढ़त हासिल कर ली है। बता दें कि पिछले साल पीजीटीआई में अपनी पहली जीत दर्ज करने वाले शौर्य (64-61-61) ने लगातार दूसरा 61 का स्कोर बनाया और दूसरे स्थान से बढ़त हासिल कर ली। श्रीलंका के एन थंगराजा (66-63-62) ने 62 का स्कोर करते हुए 16-अंडर 291 के कुल स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं हाफवे लीडर खलिन जोशी (64-60-67) ने तीसरे राउंड में 67 का स्कोर कर थंगराजा के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान बनाए रखा। बेंगलुरु के 16 वर्षीय रूकी मनोज एस (65), फरीदाबाद के अभिनव लोहान (64) और बेंगलुरु के एम धर्मा (66) 15-अंडर 192 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे। शौर्य ने फ्रंट-नाइन में तीन बर्डी और एक बोगी के साथ संतुलित प्रदर्शन किया, लेकिन बैक-नाइन में उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए छह बर्डी हासिल कीं। पार-4 के 12वें होल में उन्होंने ग्रीन ड्राइव की, दो मौकों पर गेंद को फ्लैग से एक फुट के भीतर रखा और 17वें होल में चिप-इन किया।

शराब घोटालाः पूर्व आबकारी मंत्री लखमा को नहीं मिली राहत

बिलासपुर. शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में बंद हैं। अग्रिम जमानत के लिए हाइकोर्ट में दायर याचिका पर आज जस्टिस अरविंद वर्मा की बैंच में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा, जिस पर कोर्ट ने एसीबी-ईडब्ल्यूएस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं अगली सुनवाई की तारीख 13 मार्च 2025 तय की है। बता दें कि कवासी लखमा की अग्रिम जमानत की याचिका ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में पहले ही खारिज की जा चुकी है। पूर्व मंत्री लखमा की ओर से वकील ने उन्हें निर्दोष बताते हुए झूठे मामले में फंसाने और परेशान करने का आरोप लगाया था। साथ ही ईडी को छापेमारी के दौरान उनके घर से पैसा और आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिलने की जानकारी दी थी, वहीं ईओडब्ल्यू की ओर से इस मामले में कवासी लखमा पर शराब घोटाले में हर महीने 50 लाख रुपए कमीशन सहित करीब दो करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने की मांग की थी। कथित शराब घोटाला मामले में श्वष्ठ ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 21 जनवरी को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया था।

विश्व में फैल रही है राजिम कुंभ कल्प की ख्याति

रायपुर। छत्तासगढ़ क गारयाबद ाजल में आयोजित राजिम कुंभ कल्प अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होता जा रहा है। इस वर्ष आयोजित राजिम कुंभ कल्प में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी, जिसमें देशभर के तीर्थयात्रियों के साथ विदेशी पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया। नीदरलैंड से पहली बार आए सिनिस ने कहा, यहाँ की संस्कृति और लोगों की आत्मीयता ने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। यह एक अद्भुत अनुभव है!

वहीं, इटली से आए जुबेतो और पैट्रिसिया ने कहा कि वे भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक और अलौकिक संस्कृति को करीब से देखने और समझने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, राजिम कुंभ कल्प भारतीय आस्था और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम है, जो हमें मंत्रमुग्ध कर रहा है।

नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और इटली से आए पर्यटकों ने 54 एकड़ में फैले विशाल राजिम कुंभ कल्प की भव्यता को देखकर खुशी व्यक्त का। राजाव लाचन मंदिर और त्रिवेणी संगम पर स्थित कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में उत्कीर्ण प्राचीन कलाकृतियों ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया।

विदेशी पर्यटक महाशिवरात्रि पर निकाली गई नागा साधुओं की शोभायात्रा में भी शामिल हुए और मेला क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया। विदेशी पर्यटकों ने राजिम कुंभ कल्प की साज-सज्जा और संत समागम क्षेत्र की भव्यता देखकर कहा ङ्क इट्स वंडरफुल!

विदेशी सैलानियों ने नागा साधुओं द्वारा निकाली गई शोभायात्रा और अखाड़ों के शौर्य प्रदर्शन को आश्चर्य और रोमांच से देखा। संत समागम क्षेत्र में उन्होंने विभिन्न संतों से आशीर्वाद लिया और नागा साधुओं के तपस्वी जीवन के बारे में जाना। पयटका न पूर आयाजन का भव्यता को अपने कैमरों में कैद किया और मेला घूमने आए लोगों के साथ सेल्फी भी ली।

राजिम कुंभ कल्प की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। विदेशी मेहमानों की उपस्थिति से इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिल रही है, जिससे भविष्य में और अधिक पर्यटक और श्रद्धालु आकर्षित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से राजिम कुंभ कल्प को एक भव्य, दिव्य और यादगार आयोजन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि सम्पूर्ण भारत की संस्कृति और आस्था की गौरवशाली पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहा है।

राजस्व के लंबित प्रकरण पर अजय ने अपने ही मंत्री को किया निरुत्तर

रायपुर। विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन ध्यानाकर्षण में अपने ही राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को भाजपा के वरिष्ठ सदस्य अजय चंद्राकर ने चौतरफा प्रश्नों की झड़ी लगाकर घेरा। प्रदेश के राजस्व विभाग में लगभग एक लाख उनचास हजार चार सौ इक्यासी लंबित प्रकरणों का आंक?ा बताते हुए पूछा लोक सेवा गारंटी का पालन आपका विभाग नहीं कर रहा है,आपने कितनों पर कार्यवाही की है बताएं? इसका जवाब सीधे नहीं देते हुए मंत्री ने इधर उधर की बात करना शुरू किया तो चंद्राकर ने कहा कि जब तक आप इस बात का उत्तर नहीं देंगें मैं दूसरा प्रश्न ही नहीं करूँगा। मंत्री ने गोलमोल जवाब दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि आपके प्रश्न को मैं समझ रहा हूं। पीडित पक्ष अपील करेगा तो कार्यवाही भी करेंगें। चंद्राकर ने कहा कि सरकार का भगवान ही मालिक है। अंतत: आसंदी के हस्तक्षेप पर मंत्री टंकराम वर्मा ने आश्वासन दिया कि यह वाकई चिंता का विषय है ,इस पर लंबित प्रकरणों पर ठोस कार्यवाही करेंगें। उमेश पटेल ने बताया कि मंत्री कह रहे हैं पीडित पक्ष के अपील पर कार्यवाही करेंगें। पटेल ने अपने क्षेत्र के दो प्रकरणों का उल्लेख करते हुए बताया कि अपील के बाद भी 3-4 माह हो गए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मंत्री ने इस पर भी कार्यवाही करने का आश्वासन सदन में दिया। अजय ने अपने द्वारा आरोपों के दौर में यहां तक कह दिया कि प्रदेश में लंबित प्रकरणों की स्थिति बहुत ही भयावह है। एक भी प्रकरण में किसी दोषी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी तरह चलता रहा तो प्रदेश में लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या आज से दोगुनी हो जाएगी। चंद्राकर ने भुइयांडप पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आपके नियम है कि यदि उसमें त्रुटि हो तो 7 दिन में सुधार हो जाएगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.